



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2013/भाद्र 13, 1935
No. 192] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2013/BHADRA 13, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2013

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डाक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्यायक समीक्षा ।

सं. 15/1006/2012-डीजीएडी—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाक्टाइल आयरन पाइप्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का मूल रूप से अधिरोपण दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमा-शुल्क के तहत किया गया था ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित, सीमाशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित, सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश

कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इक्टाइल आयरन पाइप्स (जिसे एतदपश्चात डीआई पाइप्स या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत दिनांक 24 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/14/2005-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी। प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं.14/14/2005-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए अपना अंतिम जांच परिणाम जारी किया था। चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इक्टाइल आयरन पाइप्स के आयातों पर भारत सरकार ने दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) में दी गई शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, यदि उसका इससे पूर्व प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, अपने अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी को यह पुनरीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरन्तरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, मैसर्स जिंदल सा लिमिटेड और मैसर्स लैन्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने घरेलू उद्योग (जिसे एतदपश्चात घरेलू उद्योग या डीआई भी कहा गया है) का गठन किया, ने प्राधिकारी के समक्ष पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के बारे में निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने के लिए एक आवेदनपत्र दायर किया। निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने के लिए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करने के लिए कि क्या दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/200-सीमाशुल्क के तहत यथाअधिसूचित मौजूदा शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने से पाटन एवं क्षति की निरन्तरता बनी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, दिनांक 7 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1006/2012 के तहत एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की।
3. और, यतः दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमा शुल्क के तहत यथा-अधिरोपित मूल पाटनरोधी शुल्क को अधिनियम की धारा 9(क) (5) में दी गई शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 41/2012-सीमाशुल्क के तहत दिनांक 12 सितम्बर, 2013 तक के लिए बढ़ा दिया है।
4. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे में विगत अधिसूचना के सभी पहलुओं को कवर किया गया है।

ख. जांच में अपनाई गई प्रक्रिया

5. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उपनियम (5) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार जांच प्रारंभ करने से पहले संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग से प्राप्त याचिका के बारे में भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को सूचना प्रेषित की।
- (ii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दिनांक 07 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की।
- (iii) प्राधिकारी ने दिनांक 07 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास, ज्ञात निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को प्रेषित की तथा उन्हें नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत का पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- (iv) प्राधिकारी ने, नियमावली के नियम 6 के उपनियम (3) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार संबद्ध देश के भारत स्थित राजदूतावास को तथा संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/विनिर्माताओं को याचिका की एक प्रति तथा निर्यातक प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की कि वे प्राधिकारी को नियत समय के अंदर संगत जानकारी उपलब्ध कराएं :
 1. यंगर्टॉन डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कंपनी लिमिटेड
 2. वेन्क्सी बेइतेई डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप कंपनी लिमिटेड
 3. बेइतेई आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 4. छेन्गडु जिन्फेंग
 5. डालियान वान्टांग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
 6. हाइडेरा मशीनरी लिमिटेड
 7. क्विआनान्शी जिन्टैंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड
 8. रिज्हाओ झुफु इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 9. शैन्डांग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड

10. शंघाई कास्ट आयरन पाइप प्लांट
 11. शैन्क्सी गुआन्गहजुआ कास्ट पाइप कंपनी लिमिटेड
 12. शैन्क्सी सालिड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
 13. जिन्जियांग ट्रेजरी इक्टाइल आयरन पाइप कंपनी लिमिटेड
 14. जिन्जिंग इक्टाइल आयरन पाइप कंपनी लिमिटेड
 15. सेंट गोबैन (जुझाऊ) पाइप कास्टिंग कंपनी लिमिटेड।
- (v) संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा संबद्ध देश के भारत स्थित राजदूतावास को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा (एमईटी) प्रश्नावली भी इस अनुरोध के साथ प्रदान कराई गई कि वे नियत समय के अंदर संगत सूचना प्राधिकारी को उपलब्ध कराएं।
- (vi) मैसर्स सेंट गोबैन (जुझाऊ) पाइप लाइन्स कंपनी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात एसजीपीएल या विदेशी उत्पादक भी कहा गया है) ने अपना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया। संबद्ध देश के किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- (vii) इसके पश्चात, एसजीपीएल ने प्रश्नावली का भाग-II काफी विलंब से अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई के उत्तरवर्ती, दायर किया।
- (viii) भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वह उस देश के उन अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को भी इस जांच की शुरुआत और निर्यातक प्रश्नावली का विहित समय के अंदर प्रत्युत्तर देने का सुझाव दें जो प्राधिकारी को ज्ञात नहीं है। पत्र, याचिका और निर्यातक प्रश्नावली, जो ज्ञात निर्यातकों को भेजी गई थी, संबद्ध देश के भारत स्थित राजदूतावास को भी भेजी गई।
- (ix) नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार विहित समय के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान कराने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को आयातक प्रश्नावली प्रेषित की गई :
1. प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 2. जे.वी. गोकल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 3. गम्माम इंडिया लिमिटेड
 4. लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड

5. एसपीएमएल इंडिया लिमिटेड

- (x) उपर्युक्त किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली अथवा जांच शुरूआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर नहीं दिया।
- (xi) यह जांच 1 अप्रैल, 2011 से शुरू करके 31 मार्च, 2012 (12 माह) तक की अवधि अर्थात् जांच की अवधि के लिए की गयी थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया।
- (xii) याचिका के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी अनुरोध करने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।
- (xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत याचिका तथा समय-समय पर किए गए अन्य प्रस्तुतिकरणों का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल में रखा और उसे नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा गया।
- (xiv) उन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रदान की, प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया।
- (xv) उत्पादन लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु विनिर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह सुनिश्चयन करने के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xvi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 28 जून, 2013 को एक मौखिक सुनवाई का आयोजन किया। इसमें घरेलू उद्योग तथा एसजीपीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर

हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों तथा प्रत्युक्तियों पर विचार किया है।

- (xvii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया। एसजीपीएल के परिसर का कोई सत्यापन दौरा नहीं किया गया क्योंकि प्राधिकारी का विचार था कि उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत को कोई निर्यात नहीं किया।
- (xviii) जांच की अवधि तथा उससे पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए और उन पर इस जांच में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया।
- (xix) इस जांच के उन अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है, सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21.08.2013 को जारी किया गया जिससे कि प्रकटन विवरण में उल्लिखित तथ्यों तथा अंतर्वस्तुओं पर अपनी टिप्पणियां और प्रस्तुतिकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का उन्हें एक और अवसर दिया जा सके ताकि अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले उन पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जा सके। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों पर गुणावगुण आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया।
- (xx) *** इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व है और प्राधिकारी द्वारा उस पर नियमों के अंतर्गत गुणावगुण आधार पर विचार किया गया है।
- (xxi) प्राधिकारी द्वारा इस जांच में अपनाई गई विनिमय दर, संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुरूप, 1 अमरीकी डालर 48.14/-रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

6. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण किए गए :-

- (i) वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुरूप मूल जांच का था। यह प्राधिकारी की संगत कार्यप्रणाली भी रही है।
- (ii) चीन जन.गण. में उत्पादित और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है और इसलिए दोनों संबद्ध वस्तुएं नियमावली के नियम 2(ख) के अनुरूप समान वस्तुएं हैं।
- (iii) संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए चीन के उत्पादकों तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

7. केवल एक प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल, चीन जन.गण. ने निम्नलिखित प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण किए :-

- (i) भारत में 1.2 मीटर के व्यास से अधिक के व्यास वाले डीआई पाइप्स का विनिर्माण नहीं किया जाता है और तदनुसार इससे अधिक के व्यास वाले ऐसे सभी पाइप्स को पाटनरोधी शुल्क की व्याप्ति से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- (ii) प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच में इस उत्पाद के दायरे सहित सभी कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है।
- (iii) उच्चतर व्यास वाले पाइपों का उत्पादन करने वाले विदेशी उत्पादक मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व के कारण भारत को निर्यात करने में अक्षम हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

3. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया गया था :-

5. विचाराधीन उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानक, के खंड 3.1 और 3.2 के अंतर्गत यथा-परिभाषित आईएसओ : 2531 (जल एवं गैस के लिए) और आईएसओ : 7186 (सीवेज अनुप्रयोगों के लिए) डक्टाइल आयरन स्पन पाइप हैं। इन्हें अक्सर स्फेरोइडल ग्रेफाइट आयरन पाइप्स अथवा डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप्स या डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यह सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के 73030030 और 73030090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

6. डीआई पाइप्स तरल पदार्थों को उच्च दबाव पर काफी लंबी दूरी तक ले जाने का काम करते हैं। इनका प्राथमिकतः प्रयोग जल या सीवर निस्तारण और गैस का परिवहन करने, घरेलू एवं औद्योगिक निस्सरण का पारेषण करने, अपतटीय एवं अभितटीय अग्निशमन प्रणाली का परिवहन करने का कार्य निष्पादित करने में किया जाता है। डीआई पाइप्स के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं -

1. उच्च दबाव पर अपरिष्कृत पीने योग्य एवं समुद्री जल का पारेषण करना।
2. पीने योग्य जल एवं गैस का वितरण करना।
3. घरेलू एवं औद्योगिक निस्सरणों का निस्तारण करना।
4. अपतटीय एवं अभितटीय अग्नि-शामक प्रणाली।

9. डक्टाइल आयरन पाइप्स को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के 73030030 और 73030090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय - अंतर्राष्ट्रीय मानक के खंड 3.1 और 3.2 के अंतर्गत, आईएसओ : 2531 (जल एवं गैस के लिए और आईएसओ : 7186 (सीवेज अनुप्रयोगों के लिए) यथापरिभाषित, डीआई पाइप्स-डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स के रूप में भी जाना जाता है। इनको अक्सर स्फेरायडल ग्रेफाइट आयरन पाइप्स या डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप्स या डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स के रूप में भी वर्णित किया जाता है। डक्टाइल आयरन पाइप्स तरल पदार्थों का उच्च दाव पर लंबी दूरी तक परिवहन करने का कार्य करते हैं। इनका प्रयोग प्राथमिकतः जल या सीवेज निस्तारण और गैस का परिवहन करने, घरेलू एवं औद्योगिक निस्सरण का परिवहन करने, अपतटीय एवं अभितटीय अग्निशामक प्रणाली का पारेषण करने के लिए किया जाता है। डीआई पाइप्स के विभिन्न अनुप्रयोग हैं अपरिष्कृत, पीने योग्य एवं समुद्री जल का उच्च दाव पर पारेषण करना, पीने योग्य जल एवं गैस का वितरण करना, घरेलू एवं औद्योगिक निस्सरण तथा अपतटीय एवं अभितटीय अग्निशामक प्रणाली का निस्तारण करना।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक ने प्रस्तुत किया है कि 1.2 मीटर और उससे अधिक के व्यास वाले डीआई पाइप्स का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है, इसलिए उच्च व्यास वाले इन सभी पाइप्स का पाटनरोधी शुल्क की अभिव्याप्ति से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायर विधिक रूप से वही रहना चाहिए जो नियमावली के नियम 23(1)(ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) में दी गई शर्तों के अनुरूप मूल जांच का था और यह ही प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप भी है।

11. प्राधिकारी ने, प्रकटन विवरण जारी होने से पहले घरेलू उद्योग तथा प्रत्युत्तरदाता निर्यातक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा उस समय प्राधिकारी को

उपलब्ध रिकार्डों तथा अन्य सूचना के आधार पर इन प्रतिवादी तर्कों की जांच की है और उसके अनुसार प्राधिकारी ने नोट किया कि (i) चीन जन.गण. से प्रत्युत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार एसजीपीएल ने जांच की अवधि, जांच की अवधि के पश्चात तथा क्षति अवधि के दौरान भारत को डीआई पाइप्स (1.2 मीटर तथा उससे अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स सहित) का निर्यात नहीं किया है; (ii) किसी अन्य आयातक अथवा विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने किसी अन्य स्रोत से डीआई पाइप्स का न तो आयात किया है और न ही इस जांच में, किसी विशिष्ट ब्यास के डीआई पाइप्स का अपवर्जन करने के अनुरोध सहित आयातक प्रश्नावली और/या किसी अन्य प्रकार के प्रस्तुतिकरण के रूप में कोई अन्य प्रत्युत्तर दिया है; (iii) साथ ही, जांच की कार्यवाही के दौरान प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि घरेलू उद्योग 1.2 मीटर और उससे अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स का विनिर्माण नहीं कर रहा है; और (iv) मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम तथा समनुरूपी सीमाशुल्क अधिसूचना में इस अधिसूचना का वर्णन सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की मद 73030030 और 73030090 के अंतर्गत आने वाले "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के रूप में किया है जो डक्टाइल आयरन आयरन पाइप्स के दायरे को किसी विशिष्ट ब्यास में सीमित नहीं करता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस जांच के संबंध में जारी प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव किया कि एसजीपीएल का तर्क त्रुटि पूर्ण है क्योंकि वर्तमान जांच केवल एक निर्णायक समीक्षा जांच है और निर्णायक समीक्षा जांच में, नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार; विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था अर्थात् सीमाशुल्क प्रशुल्क की मद संख्या 73030030 और 73030090 के अंतर्गत आने वाले सभी ब्यास के डक्टाइल आयरन पाइप्स।

12. प्राधिकारी ने एक प्रकटन विवरण जारी किया और हितबद्ध पक्षकारों से उसमें अंतर्विष्ट अंतर्वस्तु के संबंध में उनकी टिप्पणियां आमंत्रित कीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में एसजीपीएल ने 1100 मि.मी. ब्यास से अधिक के ब्यास के डीआई पाइप्स का अपवर्जन करने के लिए अपने दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

- (i) यद्यपि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग 1100 मिमी. के ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डक्टाइल आयरन पाइप्स का उत्पादन नहीं कर सकता है तथापि सेंट गोबैन यह प्रस्तुत करता है कि 1100 मिमी. के ब्यास से अधिक के ब्यास के डक्टाइल आयरन पाइप्स का उत्पादन करना घरेलू उद्योग के लिए इस कारण संभव नहीं है कि घरेलू उद्योग के पास उनका उत्पादन करने के लिए अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में जरूरी विनिर्माण सुविधाओं का अभाव है। 1100 मिमी. ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डक्टाइल आयरन पाइप्स का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित विनिर्देशनों की मशीनरी एवं संयंत्र लगाना अपेक्षित होता है। डक्टाइल आयरन पाइप का विनिर्माण करने की प्रक्रिया में एक

सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन होती है जहां द्रव धातु को सांचे में उड़ला जाता है और इसे अपेक्षित ब्यास और लम्बाई पाइप्स का उत्पादन करने के लिए उच्च गति से घुमाया जाता है। तब इन पाइप्स को सांचों से निकाला जाता है और इन्हें अभितापन भट्टी में भेजा जाता है जहां उनका ताप उपचार किया जाता है। इसके पश्चात इन पाइप्स के अंदर और बाहर दोनों ओर विशेष फिनिशिंग मशीन से कोट किया जाता है, इस मशीन में पाइप्स की लीक-प्रूफ प्रकृति की जांच करने के लिए एक निरीक्षण डिवाइस होती है। सांचे में डालने वाली मशीन, अभितापन भट्टी तथा फिनिशिंग लाइन्स कतिपय विशिष्ट रेंज के ब्यास के लिए बनी होती हैं और इस डिजाइन रेंज के बाहर पाइप्स बनाने के लिए इसे निर्धारित स्वरूप में घटा-बढ़ा लेना व्यवहार्य नहीं है। सबसे बड़ा पाइप, जिसका भारतीय उद्योग अपनी मौजूदा सुविधाओं से उत्पादन कर सकता है, वह है 1.1 मीटर। यदि वे इससे बड़े आकार के पाइप का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें सांचे में डालने वाली बड़ी मशीन, बड़ी अभितापन भट्टी और बड़ी फिनिशिंग लाइन लगानी होगी, इसका मतलब यह होगा कि पूरी तरह से नया संयंत्र लगाना। मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरियां 1100 मिमी. ब्यास वाले पाइप्स का उत्पादन करने के लिए इस प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं चला सकती हैं। इस कार्य के लिए भारी मात्रा में पूंजी व्यय की आवश्यकता न केवल उपकरणों के लिए चाहिए बल्कि भवन एवं इन मशीनों को सहारा देने के लिए भवन और उपयोगिता की अन्य वस्तुओं पर भी भारी व्यय करना होगा। इस परियोजना के निष्पादन में भी बहुत लम्बा समय लगेगा। कोई भी ग्राहक पाइप्स के आर्डर देने के लिए नए संयंत्र की स्थापना होने और उससे विनिर्माण शुरू होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता है।

- (ii) यह एक त्रुटिपूर्ण विधिक स्थिति है कि प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के दायरे की जांच नहीं कर सकते हैं। विगत में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा के दौरान विचाराधीन उत्पाद के दायरे की जांच की है। पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में प्राधिकारी ने न केवल विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा की बल्कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एक उत्पाद प्रकार को छूट भी प्रदान की थी। इस मामले में सीईएसटीएटी आदेश से पहले जारी प्रकटन विवरण में के वैल्यू 60 युक्त और 78 से अधिक के वैल्यू पीवीसी पेस्ट/ इमल्सन रेजिन को शामिल किया गया था परंतु सीईएसटीएटी आर्डर के पश्चात कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने 78 से अधिक के वैल्यू के पीवीसी पेस्ट/इमल्सन रेजिन का अपवर्जन करने की मांग की और विस्तृत जांच के पश्चात प्राधिकारी ने के वैल्यू 60 से कम के पीवीसी पेस्ट रेजिन का अपवर्जन कर दिया और के वैल्यू 78 से अधिक के पीवीसी पेस्ट रेजिन को इसमें शामिल कर दिया।

13. प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया कि वे इस समय 1200 मिमी तक के ब्यास के डी आई पाइप्स का विनिर्माण

कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए कि 1200 मिमी. ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन क्यों नहीं करना चाहिए, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं :-

- (i) वर्तमान जांच नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुरूप, केवल एक निर्णायक समीक्षा जांच है जहां विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो मूल जांच में था। किसी निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा की मांग करना न केवल एक गलत सलाह है बल्कि यह अवैध भी है।
- (ii) जहां तक प्राधिकारी के इस प्रेक्षण का सवाल है कि भारत में घरेलू उद्योग 1.2 मीटर ब्यास तथा उससे अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स का विनिर्माण नहीं करता है, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम जांच परिणाम के किसी भाग, जिसका उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, का समाधान पुनरीक्षा जांच शुरुआत अधिसूचना में नहीं किया जा सकता है। यह पाटनरोधी विधियों के विपरीत होगा। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत अधिसूचना ही दायरे को स्वतः प्रतिबंधित करती है और जो मुद्दे जांच शुरुआत अधिसूचना का भाग नहीं हैं, उनका समाधान करना न तो मुक्त है और न ही अनुमेय है। विचाराधीन उत्पाद में संशोधन करने के लिए ऐसे परिवर्तन करने होंगे जो जांच शुरुआत नोटिस का भी भाग नहीं थे। घरेलू उद्योग यह भी प्रस्तुत करना चाहता है कि यह मुद्दा वर्ष 2007 में इसकी जांच शुरुआत के समय भी मौजूद था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि भारत में कई आकार के डीआई पाइप्स का निर्माण किया जाता है जिनका ब्यास 80 मिमी. से लेकर 1100 मिमी. तक का होता है। बड़े आकार के पाइप्स का निर्माण भी किया जा सकता है। वर्ष 2007 की जांच शुरुआत के दौरान इस अभिकथन के संबंध में कोई टिप्पणी और/या आपत्ति अभिलेखबद्ध/पर्यवेक्षित नहीं की गई कि 'बड़े आकार के पाइप्स भी बनाए जा सकते हैं।' किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम जांच परिणाम के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की।
- (iii) इसके अतिरिक्त, इस समय भारत में 1200 मिमी. के ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स की कोई मांग भी नहीं है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार 1200 मिमी. ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स के लिए कोई निविदा भारतीय बाजार में अब तक नहीं निकाली गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग यह भी मानता है कि जांच की अवधि के दौरान इससे अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स का आयात भी नहीं किया गया। इस समय, भारत में घरेलू उद्योग 1200 मिमी. तक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स का उत्पादन कर रहा है क्योंकि अब तक भारत में इससे अधिक के ब्यास वाले डीआई पाइप्स की कोई मांग ही नहीं आई है। यह नोट किया जा सकता है

कि उच्चतर आकार के डीआई पाइप्स के लिए तरल धातु तथा अन्य कई सुविधाएं सामान्य (कामन) होती हैं तथा स्पिनिंग मशीन एवं अभितापन भट्टी के लिए ही कुछ अतिरिक्त निवेश की जरूरत होती है। प्रस्तुत किया गया उत्पादन चार्ट यह इंगित करता है कि किस स्तर पर अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा बोकारो, झारखंड में ग्रीन फील्ड स्टील प्रोजेक्ट अपनी स्थापना के अग्रिम स्तर पर है। इस प्रोजेक्ट में 1200 मिमी. से अधिक के आकार वाले डीआई पाइप्स का विनिर्माण किया जाना भी शामिल है। यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए भारी निवेश पहले ही कर दिया गया है। डीआई पाइप्स संयंत्र के लिए 400 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत में से लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किया जा चुका है। इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि इस तरह का कोई अपवर्जन न केवल विधि के विपरीत होगा, बल्कि यह घरेलू उद्योग के हित के लिए भी घातक सिद्ध होगा।

(v) यह पुनः स्मरण करया जा सकता है कि प्राधिकारी द्वारा एसडीएच उपस्कर (दिनांक 19-10-2010 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी) मामले में निर्धारित सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। उपर्युक्त मामले में प्राधिकारी ने (यद्यपि यह एक नवीन जांच थी फिर भी) निष्कर्ष निकाला कि जब तक कि यह सिद्ध करने के लिए कि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, जांच अवधि के दौरान भारत में उसका निर्यात नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी उत्पाद का अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। यह भी धारित किया जाता है कि यदि इस बात की पर्याप्त जांच हो चुकी हो कि संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया है तब भी उसके अपवर्जन की मांग नहीं की जा सकती है। इस मामले से यह स्पष्ट है कि यहां तक कि नई जांच में भी प्राधिकारी ने इस उत्पाद का अपवर्जन इस आधार पर नहीं किया कि इस उत्पाद का निर्यातकों द्वारा देश में निर्यात नहीं किया गया है और इस पूर्ववयव पर कि घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए भारी निवेश किया है।

14. प्राधिकारी ने इस निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में परिवर्तन करने के संबंध में इन सभी तथ्यों और प्रकटन विवरण पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरणों और पिछले पूर्वोदाहरणों की जांच की है और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है :-

(i) जहां तक प्राधिकारी द्वारा उत्पाद दायरे में परिवर्तन से संबंधित कतिपय विगत जांचों के बारे में एसजीपीएल और घरेलू उद्योग के संदर्भ का संबंध है, प्राधिकारी का विचार है कि कोई भी जांच व्यक्तिगत तथ्यों और प्रत्येक

मामले के गुणावगुण पर आयोजित की जाती है जो अलग-अलग हो सकते हैं। फिर भी, जहां तक प्रत्युत्तरदाता निर्यातक के इस तर्क का संबंध में कि ऊपर उल्लिखित वीवीसी पेस्ट/इमल्सन रेजिन के मामले में (यूरोपियन यूनियन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक सीमक्षा जांच दिनांक 04 अप्रैल, 2013 कर अंतिम जांच परिणाम .संख्या 15/27/2008-डीजीएडी) जिसमें प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में उत्पाद के दायरे में परिवर्तन/उपहासन किया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उस मामले तथा वर्तमान मामले में तथ्य अलग-अलग हैं। ऊपर उल्लिखित मामले में प्राधिकारी ने कुछ उत्पाद प्रकारों का अपवर्जन इस कारण से नहीं किया था कि घरेलू उद्योग कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण नहीं करता है बल्कि इसलिए किया था कि प्राधिकारी ने एक समानांतर जांच में (चीन जन.गण. जापान, कोरिया आरपी, मलेशिया, रूस, ताईवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में) संबंधित उत्पाद प्रकार का पहले ही अपवर्जन कर दिया था।

- (ii) जहां तक प्रत्युत्तरदाता निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि 1100 मिमी. से अधिक के ब्यास वाले डकटाइल आयरन पाइप्स का उत्पादन करना घरेलू उद्योग के लिए संभव नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित प्रकार के संयंत्र और उपकरणों के रूप में जरूरी विनिर्माण सुविधाओं का अभाव है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा कि घरेलू उद्योग केवल 1100 मिमी. तक के डीआई पाइप्स का ही विनिर्माण करता है, वर्ष 2007 की मूल जांच के समय भी मौजूद था परंतु इस अभिकथन के संबंध में कि "बड़े आकार के पाइप्स भी बनाए जा सकते हैं" कोई टिप्पणी और/या आपत्ति रिकार्डबद्ध/प्रेक्षित नहीं की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में यद्यपि घरेलू उद्योग स्पष्टतः केवल 1100 मिमी. तक के डीआई पाइप्स का ही विनिर्माण करता है, और एसजीपीएल ने यह मुद्दा उठाया है, इसलिए यह तथ्य भी है कि (i) मांग न होने के कारण न तो चीन जन.गण. के प्रत्युत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार ने जांच की अवधि में, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में और क्षति अवधि में भारत को डीआई पाइप्स (1.2 मीटर और उससे ऊपर के डीआई पाइप्स सहित) का निर्यात किया है और न ही घरेलू उद्योग ने उच्चतर ब्यास के डीआई पाइप्स का ही विनिर्माण किया है; और (ii) किसी भी आयातकर्ता अथवा किसी अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी स्रोत से डीआई पाइप्स का आयात नहीं किया है और न ही इस जांच में किसी भी तरह से न तो आयातक प्रश्नावली के जरिए और न ही किसी अन्य प्रस्तुतिकरण से, जिसमें किसी विशिष्ट ब्यास के डीआई

पाइप्स का अपवर्जन करने के लिए किया गया कोई अनुरोध भी शामिल है प्रत्युत्तर दिया है।

15. उपर्युक्त तथ्यों एवं किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा पूर्वोदाहरणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी अपने इस तर्क पर कायम रहते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा मौलानुत्क प्रशुल्क की सर गणना 73030030 और 73030090 के अंतर्गत आने वाली सभी ब्यास का इक्टाइल आकारन समान ही है।

16. किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने "समान वस्तु" के मुद्दे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित डीआई पाइप्स तथा चीन जनगण. में उत्पादित डीआई पाइप्स पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार "समान वस्तुएं" हैं।

घ घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

17. मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कॉस्टिंग्स लिमिटेड, मैसर्स जिन्दल सा लिमिटेड और मैसर्स तेंको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो घरेलू उद्योग हैं ने घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :-

- (i) आवेदनकर्ताओं द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 72 प्रतिशत है जो देश में कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा अनुपात बनता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश से आयात नहीं किया है और इस कारण वे नियम 2(ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप पात्र घरेलू उद्योग संस्थापित होते हैं।
- (ii) "आधार" के मुद्दे के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि धारा 9क(5) के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई में "आधार" की जांच लागू नहीं होती है और इस कारण यह असंगत है। ऐसा होते हुए भी, वे नियम 5 में उल्लिखित "आधार" की सभी प्रक्रिया को पूरा करते हैं।

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

18. एसजीपीएल कुल घरेलू उत्पाद में याचिकाकर्ताओं के हिस्से का विरोध नहीं कर रहा है, परंतु उसने देश में कुल मांग की संगणना करने के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है कि जब उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा 72 प्रतिशत है तो वे केवल अपने बिक्री आंकड़ों के आधार पर कुल मांग की संगणना नहीं कर सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई भी संगत प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने आवेदनकर्ताओं नामशः मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड, मैसर्स जिंदल सा लिमिटेड और मैसर्स लैन्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सूचना के गुणावगुणों की जांच की तथा वे उन्हें नियमावली के आशय के अंतर्गत वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

20. गोपनीयता के संबंध में प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) घरेलू उद्योग से अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया तथा प्राधिकारी द्वारा उन्हें उसकी अनुमति दी गई।
- (ii) घरेलू उद्योग की समेकित जानकारी को गोपनीय रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (iii) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी को गोपनीय रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

21. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) यह कि आवेदनकर्ता ने इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार नोटिस तथा विधि के उपबंधों के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है। गोपनीयता का दावा समुचित औचित्य से किया गया है और इसलिए प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है।
- (ii) इसके विपरीत, प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक ने गोपनीयता का विवरण प्रदान किए बिना, जो नियम एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक पूर्वापेक्षा है, ही स्वयं गोपनीयता का दावा किया है। गोपनीयता के किसी भी दावे की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक उस दावे के समर्थन में कोई समुचित औचित्य न दिया गया हो। विदेशी उत्पादक ने तो अपने उत्पाद विशेष और उत्पाद सूची पत्र की गोपनीयता का भी दावा किया है जिसकी नियम एवं इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के अनुरूप अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में, चूंकि विदेशी उत्पादक नियमावली के

अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने से असफल रहा है, इसलिए गोपनीयता के लिए किया गया उनका दावा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सभी सूचना को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

- (iii) एसजीपीएल ने यह प्रकटन नहीं किया है कि उनसे संबंधित एक अन्य कंपनी भी चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही है और इस दृष्टि से तो उसने प्राधिकारी से भी सूचना छिपाई है।
- (iv) गोपनीयता के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग तर्क प्रस्तुत करता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग को संघटित करने वाली तीन कंपनियों में से दो कंपनियां एक-दूसरे से संबद्ध हैं, क्षति संबंधी समेकित सूचना का भी प्रकटन नहीं किया जा सकता है। सूचना का अगोपनीय पाठ में किया गया प्रकटन प्रतिस्पर्धियों के लिए यह संभव बनाएगा कि वे एक-दूसरे का वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, कीमत से संबंधित जानकारी जैसे लगाई गई पूंजी का आवक, लाभ, नकदी प्रवाह, उत्पादन लागत, बिक्री कीमत आदि का प्रकटन करने से घरेलू उद्योग के हित में गंभीर पूर्वावधारणा कारित करेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/सूचना के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर नियम 6(7) के अनुरूप निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की तथा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावों से संतुष्ट होकर, नियमों तथा प्राधिकारी की मानक प्रक्रिया के अनुरूप, उसकी अनुमति दे दी।

च. विविध प्रस्तुतिकरण

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतिकरण

23. प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को 5 वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क का पर्याप्त संरक्षण दिया गया, इस दौरान घरेलू उद्योग को अपनी स्थिति में सुधार कर लेना चाहिए था।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

24. प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल ने जांच की कार्यवाही के दौरान कई बार प्राधिकारी को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि वे संबद्ध वस्तु के निर्यातकर्ता हैं और कई ज अन्य जगहों पर उन्होंने अपने को विदेशी उत्पादक कहा है। वास्तव में, वे यह

स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हो सके कि यदि उनकी अंतिम योजना भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करने की है तो वे शुल्क का विरोध क्यों कर रहे हैं।

25. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल ने स्वीकार किया है कि उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली का भाग-II प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग यह समझने में असमर्थ है कि वे अपने कुछ लिखित प्रस्तुतिकरणों में यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने प्राधिकारी को समस्त जानकारी प्रस्तुत कर दी है। यह डीजीएडी की संगत कार्यप्रणाली है कि वह सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई मामलों में प्राधिकारी ने सूचना को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह सूचना सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात पहली बार प्रस्तुत की गई है। जांच के विलंबित स्तर पर प्रत्युत्तर स्वीकार करना अभिवचन के सभी सिद्धांतों तथा प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत है। जहां तक एसजीपीएल के इस तर्क का संबंध है कि न तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने और न ही घरेलू उद्योग ने इतने लंबे समय तक किसी को इंगित नहीं किया, इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी दूसरे पक्ष के मत्थे मढ़ देना अत्यधिक कमजोर एवं धृष्टतापूर्ण प्रयास होता है। इसके अतिरिक्त, यह मामला अपूर्ण जानकारी का नहीं है, परंतु यह मामला विहित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने में पूर्ण असफल रहने का है। यह स्पष्ट है कि पेशेवर लोगों की सहायता लेने के बावजूद, उक्त पक्षकार ने अपने विधिक उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया। यह मामला निश्चय ही किसी गलती का नहीं है बल्कि यह मामला प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए सूचना को जानबूझकर प्रस्तुत न करने के प्रयास का है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का विस्तार न किए जाने की स्थिति में पाटन या क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना है और इस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी द्वारा सभी संगत सूचना की जांच की जाती है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर के संगत भाग-II का प्रत्युत्तर प्रदान नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रत्युत्तर निर्यातक चीन से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने वाला निश्चय ही एक बड़ा उत्पादक नहीं है और इसलिए उनका प्रश्नावली का प्रत्युत्तर किसी भी हाल में ऐसी स्थिति में जब पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने में असंयोगी नहीं है। इसलिए, उनके प्रश्नावली प्रत्युत्तर को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए पर्याप्त के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक बार जांच प्रारंभ कर दिए जाने और प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान कराने के लिए नोटिस भेजे जाने के पश्चात सभी विहित प्रपत्रों में सूचना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व हितबद्ध पक्षकारों का हो जाता है। चीन की प्रमुख कंपनियों ने अपनी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर न देकर निर्दिष्ट

प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है और इसलिए, प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, चूंकि चालू अवधि के दौरान चीन से कोई निर्यात नहीं हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी को क्षति की संभावना का निर्धारण चीन से संचयी निर्यातों के आधार पर करना पड़ा। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान समीक्षा का प्रयोजन पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता का निर्धारण करना है, और ऐसी स्थिति में जैसी कि इस समय मौजूद है जिसमें चीन से भारत को कोई निर्यात हुए ही नहीं हैं, पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण चीन से पाटित एवं क्षतिकारी आयातों की मात्रा के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः, एक ऐसी निर्णायक समीक्षा जांच में, किसी एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली प्रत्युत्तर, जहां निर्यात की मात्रा बहुत कम है, की संगतता काफी हद तक सीमित हो जाती है।

छ. पाटन का आकलन - क्रियापद्धति एवं मापदंड

पाटन मार्जिन और पाटन की सम्भाव्यता

सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

28. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

- (i) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए प्रावधान के अनुरूप किया गया है।
- (ii) इस तथ्य का निश्चय हो जाने के पश्चात कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या विनिर्मित मूल्य के आधार पर इसलिए नहीं किया जा सकता है कि संगत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी को सहयोगकर्ता उत्पादक द्वारा ऐसे तृतीय देश में की गई सभी घरेलू बिक्रियों तथा उसकी उत्पादन लागत एवं इससे जुड़ी अन्य सभी सूचना एवं साक्ष्य (व्यापार के सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध सभी जानकारी सहित) से संबंधित संपूर्ण एवं विस्तृत सत्यापन योग्य सूचना प्रदान कराना अपेक्षित होता है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 में यथा उल्लिखित पक्षपात रहित तुलना के सिद्धांत भी इस संबंध में संगत है। याचिकाकर्ता उक्त सूचना बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उत्पादक से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं।

- (iii) मूल जांच में प्राधिकारी ने चीन के किसी भी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रदान नहीं किया था और चीन में सामान्य मूल का निर्धारण, यथासंशोधित उक्त नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संबद्ध वस्तु की चीन में अनुमानित उत्पादन लागत तथा तर्कसंगत लाभ पर आधारित विनिर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस जांच में भी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने हेतु वही क्रियापद्धति अपनाने पर विचार करने का अनुरोध किया है।
- (iv) चीन में प्रस्तावित सामान्य मूल्य की संगणना भारत में, विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। डीआई पाइप्स के लिए कच्चे माल की लागत का परिकलन घरेलू उद्योग के कच्चे माल की भारत लागत के आधार पर किया गया है क्योंकि उससे ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकेत मिलता है।
- (v) जहां तक प्रत्युत्तरदाता के इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि उनकी उत्पादन लागत भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम नहीं है, इस संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि प्रत्युत्तरदाता का तर्क सत्य है तो इससे उच्चतर पाटन मार्जिन का पथ-प्रशस्त होगा। संभावित पाटन मार्जिन के उच्च स्तर से यह लगभग निश्चित है कि यदि शुल्क को हटा लिया जाता है तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि चीन के निर्यातक संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन करना पुनः प्रारंभ कर देंगे।

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

29. एकमात्र प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक एसजीपीएल ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं -

- (i) याचिकाकर्ता ने पाटन सिद्ध करने के एक प्रयास में भारी उच्चतर सामान्य मूल्य का दावा किया है जबकि की मौजूदगी है ही नहीं।
- (ii) याचिकाकर्ता ने "घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की भारत औसत लागत" पर विचार किया है जो सुस्थापित कार्यप्रणाली के स्पष्टतः विपरीत है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कच्चे माल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हैं न कि घरेलू उद्योग की खपत कीमतों पर। परंतु वर्तमान मामले में ऐसा किया जाना उस स्थिति में प्रतीत होता है जब कि एक प्रमुख कच्चे माल अर्थात् लौह अयस्क और इस उत्पाद के उत्पादन में शामिल अन्य कच्चे माल का भारी मात्रा में आयात किया जाता है।

- (iii) प्राधिकारी ने विनिर्मित सामान्य मूल्य के लिए न्यूनतम प्रभावी लागत और न्यूनतम गैर क्षतिकारी कीमत पर विचार किए जाने की संगत कार्यप्रणाली का अनुपालन नहीं किया है।
- (iv) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और आगे पुनः दावा किया कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः चीन में प्रचलित कीमतें याचिकाकर्ता के लिए पूर्णतः असंगत हैं और फिर भी याचिकाकर्ता चीन की लागत पर विचार करते हुए ही आगे बढ़े हैं।
- (v) सामान्य मूल्य का त्रुटिपूर्ण एवं बढ़ा-चढ़ाकर परिकलन उस कीमत से जिसपर घरेलू उद्योग कतर, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को निर्यात कर रहा है अथवा प्रचलित बाजार कीमतों से तुलना करने पर और भी स्पष्ट हो जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

30. इस जांच में कार्यवाही के एक भाग के रूप में, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां यह सुझाव देते हुए भेजी कि वे निर्धारित ढंग एवं स्वरूप में जानकारी उपलब्ध कराएं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इन प्रश्नावलियों का न तो कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और न ही चीन के किसी बड़े उत्पादक/निर्यातक, एसजीपीएल को छोड़कर, ने कोई प्रस्तुतिकरण ही किया। केवल एसजीपीएल, जो संयोगवश चीन से अन्य देशों को निर्यात के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी नहीं है, ने प्रत्युत्तर दिया और वह भी आधा-अधूरा प्रत्युत्तर मौखिक सुनवाई के बाद दिया गया। यह भी नोट किया जाता है कि एसजीपीएल ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। चीन की प्रमुख कंपनियों ने अपनी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर न देकर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है और इसलिए, प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण चीन से संचयी निर्यातों के आधार पर करना पड़ा। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान समीक्षा का प्रयोजन पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता का निर्धारण करना है, और ऐसी स्थिति में जैसी कि इस समय मौजूद है जिसमें चीन से भारत को कोई निर्यात हुए ही नहीं है, पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण चीन से पाटित एवं क्षतिकारी आयातों की मात्रा के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः, एक ऐसी निर्णायक समीक्षा मामले में, किसी एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली प्रत्युत्तर, जहां निर्यात हुआ ही नहीं है, की संगतता सीमित हो जाती है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. को, किसी निर्यातकर्ता देश या व्यक्तिगत निर्यातक/उत्पादक द्वारा पाटनरोधी

नियमावली के अनुसार इस पूर्ववधारणा के खंडन के अध्यक्षीन, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना है।

32. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली धारणा का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक (निर्यातकर्ताओं/उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं और इस धारणा के विपरीत तथ्य स्थापित कर दिए जाते हैं। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ताकि प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या :

- (i) चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का कीमत, लागत और कच्चे माल सहित अंतरनिविष्टियों, प्रौद्योगिकी की लागत, श्रम, आउटपुट, बिक्रियाँ और निवेश संबंधी निर्णय उन बाजार संकेतकों के अनुरूप लिए गए हैं जिनमें मांग एवं आपूर्ति का प्रतिबिम्बन होता है और जो इस संबंध में देश के किसी हस्तक्षेप के बिना किया गया है और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित कर रही है;
- (ii) इन फर्मों की उत्पादन लागत तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा, खासकर परिसंपत्तियों का मूल्यहास, बड़े खाते में डाले गए अन्य, विनिमय प्रणाली तथा ऋणों की प्रतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में की गई विकृतियों के अध्यक्षीन हैं;
- (iii) यह फर्म दिवालियापन और संपत्ति विधियों के अध्यक्षीन होती हैं जो इन फर्मों का प्रचालन करने के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती हैं।
- (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है।

33. यह नोट किया जाता है कि एसजीपीएल को छोड़कर चीन के अन्य किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने न तो विहित प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर दिया है और न ही संपूर्ण प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर दिया है और न ही संपूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर भेजा है। एसजीपीएल ने आंशिक जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, यह कंपनी चीन से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने वाली एक बड़ी कंपनी नहीं है। चीन के निर्यातकों/उत्पादकों से सहयोग के अभाव में एकमात्र प्रत्युत्तरदाता, नामशः एसजीपीएल द्वारा प्रस्तुत आंशिक जानकारी को संज्ञान में लेना उपयुक्त नहीं होगा। अतः, प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं।

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 07 में प्रावधान है कि -

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से किए गए आयात मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या विनिर्मित मूल्य, या ऐसे किसी तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां यह संभव न हो वहां किसी अन्य संगत आधार, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, भारत में समान उत्पाद के लिए, यदि जरूरी हुआ तो विधिवत समायोजित करके, वास्तविक रूप से प्रदत्त या भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर तथा प्रश्नाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन किया जाएगा और उनका चयन करते समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। समान मामले में किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में की गई जांच पर भी, जहां कहीं उचित समझा गया, निर्धारित समय सीमा के अंदर विचार किया जाएगा। इस जांच के पक्षकारों को उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के चयन के बारे में सूचना अविलंब प्रदान कराई जाएगी और उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए उन्हें समुचित समयावधि दी जाएगी।"

35. जहां तक एसजीपीएल द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर और उनके द्वारा दावाकृत बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में पाटन एवं क्षति की संभावना चीन से संचयी निर्यातों पर आधारित है और यह चीन की किसी एक कंपनी के निर्यातों पर आधारित नहीं हो सकती है। अतः, प्राधिकारी ने एसजीपीएल के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया है। एसजीपीएल द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिए जाने का दावा केवल तभी संगत होगा यदि प्राधिकारी एसजीपीएल के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। भारत को किसी निर्यात के अभाव में प्राधिकारी ने चीन के निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है। अतः, एसजीपीएल द्वारा दावाकृत बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा और सामान्य मूल्य चीन के बड़े निर्यातकों से प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में असंगत है। पाटनरोधी नियमावली के अखंडित रहते हुए प्राधिकारी ने विनिर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण, पूर्वोल्लिखित कारणों की वजह से, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विधियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण "कोई अन्य संगत आधार" विधि को अपनाकर किया है।

36. प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ सर्वाधिक कार्यकुशल घरेलू उत्पादक के खपत मानदंडों, परिवर्तन लागत और एसजीए पर भरोसा किया है। विनिर्मित सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पादन लागत के 5 प्रतिशत की दर से

लाभ जोड़ा गया है। यह तरीका अपनाकर विनिर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण *** अमरीकी डालर प्रति मी. टन के रूप में किया जाता है।

निर्यात कीमत

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि में संबद्ध देश से भारत को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया गया है। चीन से प्रत्युत्पत्ता उत्पादक/निर्यातक एसजीपीएल सहित चीन के किसी भी निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात किए जाने के अभाव में प्राधिकारी जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने में असमर्थ रहे हैं।

पाटन मार्जिन

38. चूंकि जांच की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि में संबद्ध देश से भारत को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने में समर्थ नहीं हो गए हैं।

क्षति का आकलन एवं कारणोत्पत्तिक संबंधों की जांच

क्षति का आकलन

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

39. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं -

(i) चूंकि संबद्ध वस्तु का क्षति अवधि या क्षति जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किया गया है, इसलिए संभवतः मौजूदा क्षति का कोई क्षति विश्लेषण कर पाना संभव नहीं है। किसी भी हाल में, वर्तमान क्षति का विश्लेषण किसी निष्पायक समीक्षा में, खासकर तब, जब कोई आयात न किया गया हो, तो महत्वहीन हो जाता है।

(ii) इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी के लिए विधि 38, अधिवक्ता प्रा. 38(5) में यथा-परिकल्पित संभावना का विश्लेषण करना कि इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग चीन के निर्यातकों द्वारा इस अवधि के दौरान अन्य देशों को किए गए निर्यात के आंकड़े ही संग्रहित करने में सक्षम हुआ है। इस संबंध में उद्योग संकेत हैं कि यदि अन्य देशों को निर्यात कीमत की भारत को अनुमानित निर्यात कीमत के अनुमान (एक बार पाटनरोधी शुल्क समाप्त का दिए जाने पर) के रूप में लिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा

कि चीन के निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति होगी। कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयण यह व्यक्त करेगा कि यदि शुल्क को बढ़ाया नहीं जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति आसन्न है।

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

40. एसजीपीएल ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं -

- (i) घरेलू उद्योग को क्षति आंतरिक प्रतिस्पर्धा तथा कुछ अन्य कारकों जैसे कोयले की अनुपलब्धता, परियोजनाओं में विलंब आदि के कारण हो रही है। घरेलू उद्योग ने, उनको हुई वर्तमान क्षति पर कोई टिप्पणी किए बिना, सीधे ही क्षति की संभावना की कल्पना कर ली। पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि संबद्ध वस्तु के भारत को आयात किए ही नहीं गए हैं।
- (ii) एसजीपीएल ने इसके आगे प्रस्तुत किया कि यदि घरेलू उद्योग चीन से निर्यातों की कीमतों से तुलना करता है तो उसकी लाभप्रदयकता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, एसजीपीएल ने प्रस्तुतिकरण किया कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से लाभप्रदायकता में गिरावट आ सकती है क्योंकि उनके आयातों की संभावित उतराई कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक होगी।
- (iii) एसजीपीएल द्वारा भविष्य में किए गए आयातों से बाजार में कीमत निग्रहण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग भारी अधिशेष क्षमता और बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा के कारण कभी भी गैर-क्षतिकारी कीमत पर नहीं पहुंच पाएगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध वस्तु के आयात न तो जांच की अवधि के दौरान और न ही क्षति जांच अवधि के दौरान किए गए हैं। अतः, प्राधिकारी का जोर पाटन एवं क्षति की संभावना का विश्लेषण करने पर है। प्राधिकारी ने मौजूदा क्षति की तुलना में कारणों का विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसजीपीएल ने संपूर्णक्षति जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया है और न ही उसने प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित आंकड़े निहित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत किए।

पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव तथा कीमत प्रभाव

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमानुसार प्राधिकारी को कीमत अधोरदन/कीमत अधोबिक्रयण/कीमत निग्रहण/कीमत अवमंदन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक पैरामीटर

43. नियमावली का अनुबंध-II अपेक्षा करता है कि क्षति के निर्धारण में इन आयातों का संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच करना अंतर्गस्त होता है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के अनुबंध-II (IV) में निम्नवत निर्धारित किया गया है :

संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनाकों का मूल्यांकन शामिल होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव होता है, जिनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल होते हैं।"

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री

44. चूंकि संबद्ध वस्तु का संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है इसलिए घरेलू उत्पादन की मात्रा तथा घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के रूप में नहीं की जा सकती है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा निम्नलिखित हैं :-

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 (जांच की अवधि)
क्षमता-घरेलू उद्योग	मी. टन	760000	760000	760000	805000
उत्पादन - घरेलू उद्योग	मी. टन	626955	661231	668004	641504
उत्पादन - अन्य	मी. टन	47401	67627	128309	250000
क्षमता उपयोग- घरेलू उद्योग	%	82%	87%	88%	80%
घरेलू बिक्री - घरेलू उद्योग	मी. टन	526608	554930	532699	459512
घरेलू बिक्री - अन्य	मी. टन	31518	67527	107701	205116
सभी स्रोतों से आयात	मी. टन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्यात बिक्री - घरेलू उद्योग	मी. टन	***	***	***	***
कुल मांग (मी. टन)	मी. टन	558126	622456	640400	664628

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (i) घरेलू उद्योग ने भारत में इस उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की। आधार वर्ष अर्थात् वर्ष 2008-09 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है।
- (ii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।
- (iii) प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई।
- (iv) यह भी देखा जाता है कि भारत में अन्य उत्पादकों का उत्पादन भी आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ा है।

लाभ, निवेश पर अर्जन और नकद लाभ

46. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री से अर्जित निवेश पर आवक, लाभ और नकद लाभ निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
लाभ/हानि प्रति यूनिट	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	288	173	-29
घरेलू बिक्री पर लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	303	175	-25
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	217	141	14
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	249	159	2
निवेश पर आवक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	255	211	15

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (i) घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में वर्ष 2009-10 में सुधार हुआ और फिर 2010-11 में उसमें गिरावट आई और जांच की अवधि में पुनः इसमें गिरावट आई।

(ii) नकद लाभ तथा निवेश पर अर्जन के मामले में भी समान प्रवृत्ति पाई गई।

रोजगार, वेतन एवं उत्पादकता

48. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या, उनको दिया गया वेतन तथा उसकी उत्पादकता निम्नवत दर्शायी गई है :-

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	109	84
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	113	133	128
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	105.	98	121
उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन/दिन	***	***	***	***

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि -

- प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता प्रतिदिन भी बढ़ी है। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में उसमें गिरावट आई है।
- कर्मचारियों को प्रदान किए गए वेतन में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि जांच की अवधि के दौरान प्रदत्त समग्र वेतन में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

मालसूची

50. घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	122	181	291

51. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई।

पाटन मार्जिन का विस्तार

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन की जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं हुआ था। तथापि, इस अंतिम जांच परिणाम के बाद वाले हिस्से में पाटन की संभावना का विश्लेषण किया गया है।

पूंजी उगाहने की क्षमता

53. यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो घरेलू उद्योग की स्थिति और भी अधिक बदतर हो जाएगी क्योंकि इससे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं और निर्यातकों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन पाटित आयातों पर करने की प्रेरणा मिलेगी। अतः, घरेलू उद्योग को बाजार या वित्तीय संस्थानों से पूंजी उगाहने की गंभीर समस्या का सामना करना होगा।

54. याचिकाकर्ता कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं। तथापि, वर्तमान विश्लेषण केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है और अन्य उत्पादों के कार्यनिष्पादन का विचाराधीन उत्पाद के कार्यनिष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वृद्धि

55. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा मांग, लाभप्रदायकता और आरओसी के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है :

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	जॉच की अवधि
उत्पादन (%)	-	5.5%	1.0%	-4.0%
बिक्री (%)	-	5.4%	-4.0%	-13.7%
बाजार हिस्सा (%)	-	-5.5%	-6.7%	-16.9%
मांग (%)	-	11.5%	2.9%	3.8%
लाभप्रदायकता(लाख रुपयों में)(%)	-	203.2%	-42.2%	-114.3%
आरओसी (%)	-	154.8%	-17.0%	92.7%

कारणात्मक संबंधों की जांच

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

56. घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि :

- विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंधों का विश्लेषण किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान मैक्सिको से आयत कंट्री ट्यूबुलर गुड्स के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के एक उद्धरण की ओर आकृष्ट किया है (डब्ल्यूटी/डीएस 282/एबी/आर, दिनांक 2 नवम्बर, 2005)।

"118. अतः हम मैक्सिको से सहमत हैं कि यह मौलिक सिद्धांत जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के विभिन्न उपबंधों में अभिव्यक्त है। संयुक्त राष्ट्र इस सिद्धांत पर समान रूप से प्रश्न चिह्न नहीं

लगाता है। तथापि, इसका आशय यह नहीं है कि पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों की स्थापना की समीक्षा" पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत नए सिरे से कसया जाना अपेक्षित है। यह इस कारण है कि अनुच्छेद 11.3 में विचारित "समीक्षा" एक "पृथक" प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मूल जांच से "भिन्न" है।

119. अपीलीय निकाय ने बल देते हुए कहा है कि, "निर्णायक समीक्षा में किए जाने वाले निर्धारण की प्रकृति मूल जांच में किए जाने वाले निर्धारण की प्रकृति से कुछ अनिवार्य रूप से पृथक होती है" और यह कि "मूल जांच में लागू सिद्धांत, स्वतः ही समीक्षा प्रक्रिया में नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं।"

X. जांच परिणाम एवं निष्कर्ष

219. इस रिपोर्ट में निर्धारित किए गए कारणों के लिए, अपीलीय निकाय :

(क) कार्यकारण संबंधों के बारे में :

(i) यह उपपादित करता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा निर्धारण में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कार्यकारण संबंधों की मौजूदगी को, एक विधिक बाध्यता के रूप में, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती है और यह कि यूएसआईटीसी को इस विवाद के निर्णायक समीक्षा मुद्दे में क्षति की संभावना का निर्धारण करने में ऐसे संबंधों को अभिव्यक्त करना अपेक्षित नहीं है।

(ii) पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा मामले में कारणात्मक संबंधों की जरूरत को लागू न करने के कई अच्छे तकनीकी एवं तार्किक कारण हैं। यदि आयात न होने पर भी शुल्क की अवधि को बढ़ाया जा सकता है तो कार्य-कारण संबंधों का विश्लेषण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, धारा 9क(5) के अंतर्गत शुल्क की अवधि बढ़ाए जाने के लिए जांच में केवल यह जांच करना होता है कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

प्रत्युत्तर विदेशी उत्पादक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की है क्योंकि निर्णायक समीक्षा मामलों में यह अधिदेशित नहीं है। यह अधिगम डीजीएडी की सुस्थापित कार्य-करण प्रणाली के विपरीत है। इसको देखते हुए प्रत्युत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार, प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वह डीजीएडी द्वारा प्रत्येक मामले में अपनाई जाने वाली संगत प्रक्रिया का अनुसरण करें।

इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयात न होने के बावजूद वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

58. नियमावली के अनुबंध-2 में कारणात्मक संबंधों के बारे में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

"यह प्रदर्शित होना चाहिए कि पाटित आयात, पाटन के प्रभाव के जरिए, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ (ii) और (iv) में उल्लिखित हैं, घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रही है। पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित संगत साक्ष्यों की जांच पर आधारित होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ऐसे ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे जो, उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं उन आयातों की मात्रा और कीमत जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई है, मांग में संकुचन अथवा खपत की प्रणाली में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा उनकी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी में विकास एवं निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता।

59. जहां तक अन्य कारकों द्वारा कारित की गई क्षति का संबंध है, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं :

उन आयातों की मात्रा एवं मूल्य जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई :

60. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का संपूर्ण क्षति अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से भी कोई आयात नहीं हुआ। अतः, आयातों की मात्रा, एवं मूल्य तथा घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

मांग में संकुचन

61. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। उसके बजाय, इसमें वृद्धि हुई है और इसने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। अतः, मांग में संकुचन वह संभावित कारण नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है कि मांग में कमी होने की संभावना है।

खपत की प्रणाली में परिवर्तन

62. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की खपत की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की प्रणाली में परिवर्तन द्वारा घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंचाने की संभावना नहीं है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

63. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जो घरेलू की क्षति में अपना योगदान दे सकती हो। यह भी देखा जाता है कि भारत में अन्य उत्पादकों के उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट अन्य घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के कारण आई है।

प्रौद्योगिकी में विकास

64. इस उत्पाद के उत्पादन के प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन न तो हुआ है और न ही निकट भविष्य में उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

निर्यात निष्पादन

65. याचिकाकर्ता कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करती हैं। तथापि, क्षति का आकलन करने के लिए केवल घरेलू बिक्रियों से संबंधित जानकारी पर ही विचार किया गया है।

झ. संभावित निर्यात कीमत, पाटन की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

66. संभावित निर्यात कीमत, पाटन की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

- (i) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के विपरीत प्रभावों² से घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए वर्तमान शुल्क को जारी रखना जरूरी है। चूंकि, जांच की अवधि के दौरान अथवा विगत वर्षों में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं हुआ है, तथापि, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि प्राधिकारी को चीन से समुचित तृतीय देशों को उक्त वस्तु की निर्यात कीमत के आधार पर भारत को संभावित निर्यात कीमत का निर्धारण करने की जरूरत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सऊदी अरेबिया को निर्यात कीमत को सर्वाधिक उपयुक्त कीमत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि चीन अपने डीआई

पाइप्स के लिए निर्यात का 32 प्रतिशत निर्यात सऊदी अरेबिया को करता है और जल वितरण का महत्व दोनों देशों में समान है। इसी तरह, घरेलू उद्योग ने भारत को संभावित निर्यात कीमत के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश को निर्यात कीमतों पर भी विचार किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन देशों, जो भौगोलिक रूप से समान क्षेत्र में हैं, को कीमतें भी तुलनीय हैं, यद्यपि इन देशों को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा बहुत कम है। बिना किसी पूर्वाग्रह के घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत को संभावित निर्यात कीमत का आकलन करने के रूप में शेष विश्व की भारत औसत निर्यात कीमत पर विचार करने की विदेशी उत्पादक की प्रतिज्ञा का कोई विधिक अथवा आर्थिक औचित्य नहीं है। पाटनरोधी नियमावली और विधिशास्त्र में पर्याप्त प्रावधान है कि जब तृतीय देश की कीमतों पर विचार करने का प्रश्न आता है तो उपयुक्तता ही वह प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किया जा सकता है।

- (ii) उक्त विदेशी उत्पादक ने स्वीकार किया है कि वे चीन के बड़े निर्यातक नहीं हैं। अतः, उनके प्रस्तुतिकरणों/सूचना का कोई महत्व नहीं हो सकता है क्योंकि इसे भारत को संभावित निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए चीन से प्रतिनिधिक आंकड़ों के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (iii) निर्यात कीमत का परिकलन डीजीएडी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप ही किया गया है। इसके अतिरिक्त, उतराई मूल्य पर पहुंचने के लिए, घरेलू उद्योग ने सामुद्रिक भाड़ा, बीमा, उतराई प्रभार और पोत पर्यन्त निःशुल्क तक सीमाशुल्क को जोड़ा है। फैक्टरी-बाह्य कीमत पर पहुंचने के लिए उसी समुद्री भाड़े और बीमा को घटाया गया है। अतः, संबद्ध वस्तु की चीन में फैक्टरी-बाह्य कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त की गई प्रणाली त्रुटि पूर्ण नहीं है।
- (iv) चीन के पास भारी उत्पादन क्षमता है जिससे भारत में संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चीन ने अपनी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि भी की है। केवल यह क्षमता संवर्धन ही घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक है। इसके अतिरिक्त, भारी क्षमता संवर्धन अभी होना बाकी है।
- (v) अन्य देशों को निर्यात कीमतें चीन से निर्यातकों के संभावित व्यवहार को स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। पुनश्च, एकमात्र प्रत्युत्तर दाता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री भारत में घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर करेंगे जिससे कि वे भारतीय

बाजार पर अपना आधिपत्य कर सकें। ऐसा मामला होने की स्थिति में कीमत अधोरदन का संवर्धित स्तर आसन्न है।

- (vi) संभावित निर्यात कीमत के आधार पर परिकलित पाटन मार्जिन 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की रेंज में है। ऐसी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग की स्थिति और अधिक खराब होगी क्योंकि इससे पाटित आयातों के उन्मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा जिसका घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बाजार हिस्सा और अंततः घरेलू उद्योग के लाभ पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा।
- (vii) चीन में उपलब्ध भारी अधिशेष क्षमता और कम कीमत, जिन पर संबद्ध वस्तु की अन्य देशों को आपूर्ति की जा रही है, से यह स्पष्ट है कि भारत में घरेलू उत्पादकों के पास अपनी कीमतें चीन की कीमतों के बराबर करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। चीन की निर्यात सांख्यिकी के अनुसार, सऊदी अरेबिया को एकओबी कीमत 36190 रुपए प्रति मी.टन है। उतराई मूल्य के अन्य तत्वों, नामशः भाड़ा, प्रहस्तन प्रभार और आधारभूत सीमाशुल्क, को जोड़ने पर उतराई मूल्य 40472 रुपए प्रति मी.टन बैठता है। उक्त अनुमानित उतराई मूल्य में 36 प्रतिशत का भारी कीमत अधोदिक्रयण तथा 11 प्रतिशत का कीमत अधोरदन शामिल है।
- (viii) यदि पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका जैसे देशों को निर्यात कीमतों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है तो भी वही स्थिति उभर कर सामने आएगी।
- (ix) यदि वस्तुओं की बिक्री संभावित उतराई कीमत पर की जाती है तो यह आसन्न है कि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्रियों पर भारी घाटा सहन करना होगा। अतः पाटन की पुनरावृत्ति और क्षति की निरंतरता तथा घरेलू उद्योग की कीमतों पर क्षतिकारी प्रभाव की संभावना आसन्न है।
- (x) घरेलू उद्योग पुनः उल्लेख करता है कि चीन के उत्पाद, जब तक वे पाटन प्रक्रियाएं नहीं अपनाते हैं तब तक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्तर सीआईएफ मूल्य का केवल 15 प्रतिशत है जो किसी भी मानक रूप से नाममात्र का है। इसके बावजूद, किसी भी निर्यातक ने संबद्ध वस्तु का न तो निर्यात किया है और न ही यहकी द्वारा निकाले गए किसी भी टेंडर में उन्होंने भागीदारी की है। अंत में, यदि उक्त निर्यातक का अभिव्यक्त उद्देश्य अन्ततः भारत में विनिर्माण सुविधा की स्थापना करना है तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे पाटनरोधी शुल्क को

विरोध करने के इच्छुक क्यों हैं। सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने के बावजूद एसजीपीएल इस मुद्दे पर शांत क्यों है। इससे उक्त पक्षकार का प्रछन्न एवं जघन्य इरादा स्वयं सिद्ध हो जाता है।

प्रत्युत्तरदाता विदेशी उत्पादक द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

67. संभावित निर्यात कीमत, पाटन की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना और क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में एसजीपीएल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया गया है :-

- (i) भारत को संभावित निर्यात कीमत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए कुछ चुनिंदा देशों की निर्यात कीमत पर विचार करने के बजाय, चीन से शेष विश्व को किए गए निर्यातों की भारित औसत कीमत पर विचार करना चाहिए।
- (ii) घरेलू उद्योग को संभावित क्षति और पाटन सिद्ध करने के लिए किए गए परिकलन समुचित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किए जाने के बजाय केवल कल्पना पर आधारित है।
- (iii) निर्यात कीमत का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग ने चीन की कुछ एजेंसियों से संग्रहित एफओबी आयात आंकड़ों से समुद्री भाड़ा और बीमा को कम कर दिया है।
- (iv) घरेलू उद्योग ने चीन के निर्यातकों के पास उपलब्ध बेशी क्षमता के संबंध में कोई स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं किया है और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या वे मौजूदा क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं या अगले 1 या 2 वर्ष में होने वाली क्षमता के बारे में। चीन में बेशी क्षमता को सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षमता, उत्पादन आदि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।
- (v) एसजीपीएल बड़ा निर्यातक नहीं है और इस कारण, एक बार पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में वह पाटन के क्रियाकलाप नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, वे उत्पाद के दायरे से केवल उच्चतर ब्याज के पाइप्स का अपवर्जन करना चाहते हैं।
- (vi) घरेलू उद्योग ने क्षति की निरंतरता और उसकी पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करने के लिए कोई वैध साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

- (vii) सेंट गोबैन चीन का एक बड़ा निर्यातक नहीं है। वह केवल सीड विपणन के लिए उच्चतर ब्यास वाले पाइपों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करना चाहता है। वे इस बात को पुनः स्वीकार करते हैं कि उन्हें संबद्ध वस्तु की भारतीय बाजार में पाटन करने से कोई बड़ा कीमत लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (viii) संभारतंत्रीय दिक्कतों के कारण भारत को डीआई पाइप्स का निर्यात करना बहुत मुश्किल है। सेंट गोबैन केवल उच्चतर ब्यास वाली उस संबद्ध वस्तु का ही निर्यात करना चाहता है, जिसका, उनके अनुसार, भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है।
- (ix) पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी अन्य देश ने चीन से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित नहीं किया है। अतः, शुल्क की अवधि को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
- (x) घरेलू उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत कीमत आकृष्ट करने वाली बाजार नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उत्पादकों की तुलना में चीन के उत्पाद अधिक मंहगे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सर्वाधिक संभव है कि कोई भी भारतीय उपभोक्ता चीन से संबद्ध वस्तु का क्रय नहीं करेगा। यहां तक कि भारतीय बाजार में प्रस्तुत की जा रही इतनी कम कीमत तथा सीमाशुल्क एवं भाड़े को ध्यान में रखते हुए चीन के किसी भी निर्यातक को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. यद्यपि एसजीपीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने उनके प्रस्तुतिकरण का समाधान संगत समझी गई सीमा तक किया है।

69. वर्तमान जांच में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संबद्ध देश से, एसजीपीएल को छोड़कर, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। केवल एसजीपीएल ने, जो अन्य देशों के लिए चीन का बड़ा निर्यातक नहीं है, अपना प्रत्युत्तर दायर किया है। तथापि, चूंकि यह कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक बड़ी निर्यातक कंपनी नहीं है और इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए पाटित कीमतों पर किए गए निर्यात की मात्रा तथा क्षतिकारी कीमतों पर किए गए निर्यात की मात्रा पर विचार करना अपेक्षित होता है और इस सीमा तक व्यक्ति प्रश्नावली प्रत्युत्तर का सीमित परिणाम होता है। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण चीन से संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों को किए गए कुल निर्यातों के आधार पर किया जाना अपेक्षित होता है।

70. इसके अतिरिक्त, एसजीपीएल की अपनी स्वीकृति के अनुसार, वे संबद्ध वस्तु के बड़े निर्यातक नहीं हैं। अतः, एसजीपीएल के कीमत आंकड़ों को अन्य प्रमुख उत्पादकों के संभावित व्यवहार, यदि इसे एक निर्णायक कारक माना जाए, के संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसजीपीएल के आंकड़ों और सूचना को संभावित क्षति का विश्लेषण करने के लिए प्रतिनिधिक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

71. अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों ने, जो प्राधिकारी को बहुमूल्य सूचना प्रदान कर सकते हैं, संज्ञान जांच में प्राधिकारी को सहयोग न करने को वरीयता प्रदान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस निर्णायक समीक्षा जांच में, जहां संभावना का आकलन किया जाना अपेक्षित होता है, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त संगत सूचना अधिक महत्वपूर्ण होती है।

72. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत को रिपोर्ट किया गया कोई भी आयात भारतीय उत्पादों के आंकड़ों के अनुरूप अथवा गौण स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों में रिपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने भारत को संभावित निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए एचएस इंटरनेशनल इंक (impexp.com) सिडनी, आस्ट्रेलिया के आयात आंकड़ों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सऊदी अरेबिया की निर्यात कीमत को प्राधिकारी द्वारा उपयोग उपयुक्त कीमत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि चीन अपने कुल डीआईए के अंतर्गत के 32 प्रतिशत का निर्यात सऊदी अरेबिया को करता है और दोनों देशों में जल परिवहन का महत्व एक समान है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण में कोई अच्छाई नहीं पायी और उन्होंने एचएस इंटरनेशनल इंक (impexp.com) सिडनी, आस्ट्रेलिया के संव्यवहार-बार निर्यात आंकड़ों के अनुरूप विश्व निर्यात पर विचार किया है। जहां तक एसजीपीएल का इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि भारत को संभावित निर्यात कीमत का आकलन करने के प्रयोजनार्थ शेष विश्व को भारित औसत कीमत पर ही विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से वैश्विक रूप से किए जाने वाले निर्यातों की भारित औसत कीमत सामान्य मूल्य से अधिक होते हुए भी इसका आशय यह नहीं है कि निर्यातों शुरूक समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन से पाटन की संभावना नहीं रहेगी, जिसका प्रतीक स्थिति में जहां इन निर्यातों का भारी हिस्सा पाटित कीमतों पर किया गया है और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। अतः निर्यातों की भारित औसत कीमत का निर्धारण पर किया गया कोई निर्धारण काफी भ्रामक हो सकता है। वर्तमान मामले के तथ्य, निर्यात में यह स्थापित करते हैं कि निर्यातों की भारित औसत कीमत सामान्य मूल्य से अधिक होते हुए भी इन निर्यातों का एक बड़ा भाग पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर हुआ है। अतः प्राधिकारी चीन से अन्य सभी देशों (भारत को छोड़कर) का पाटित एवं क्षतिकारी सौदों का औसत निर्यात कीमत को ध्यान में लेने का विचार करते हैं।

73. प्राधिकारी, घरेलू उद्योग द्वारा एचएस इंटरनेशनल इंक (impexp.com) सिडनी, आस्ट्रेलिया से प्रस्तुत संव्यवहार-बार निर्यात आंकड़ों के आधार पर चीन से सभी देशों को निर्यात की (अथवा) किए गए पाटित एवं क्षतिकारी संव्यवहार की औसत निर्यात कीमत पर

विचार करते हैं। प्राधिकारी ने यह तरीका भारत को वास्तविक निर्यात के अभाव के कारण अपनाया है, प्राधिकारी उस संभावित निर्यात कीमत का निर्धारण कर रहे हैं जिस पर संबद्ध वस्तु, यदि उसका भारत की ओर दिग्परिवर्तन किया जाता है तो, द्वारा घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति किए जाने की संभावना है।

74. प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. से निर्यातों की संभावित फैक्टरी-बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण अंतरदेशीय भाड़ा एवं बीजा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और मूल्यवर्धित कर के समायोजन का संभावित निवल निर्यात कीमत के साथ समायोजन करके किया गया है। यह समायोजन करने के पश्चात संभावित समायोजित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

जांच की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन

	अमरीकी डालर (प्रति मी.टन)
सामान्य मूल्य	***
निवल निर्यात कीमत	***
संभावित पाटन मार्जिन	***
संभावित पाटन मार्जिन %	***
संभावित पाटन मार्जिन % रेंज	0-10

75. पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा एचएस इंटरनेशनल इंक (impexp.com) सिडनी, आस्ट्रेलिया द्वारा यथा प्रस्तुत, चीन के उत्पादकों की भारत के अलावा अन्य देशों को संव्यवहार-बार निर्यात कीमत का विश्लेषण किया है।

76. प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों/सूचना से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान 39196 रूपए प्रति मी.टन की औसत एफओबी कीमत पर चीन जन.गण. से अन्य देशों को निर्यात की कुल मात्रा 488530 मी.टन थी, इसमें से 1,13,641 मी.टन (23 प्रतिशत) निर्यात पाटित कीमतों पर तथा घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमतों से कम कीमत पर किया गया था। जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु की मांग 664628 मी.टन थी। चीन के कुल निर्यातों में से 23 प्रतिशत निर्यात जो पाटित तथा क्षतिकारी कीमतों पर किए गए थे, भारत में कुल मांग का 17 प्रतिशत बैठता है। यह 17 प्रतिशत भारी मात्रा है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इसका भारी महत्व है चीन में अत्यधिक क्षमता उपलब्ध है; फिर भी चीन के किसी भी बड़े उत्पादक/निर्यातक ने तथा भारत में किसी भी आयातक ने इस जांच में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और यदि भारत की कुल मांग को देखा जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो भारत को पाटित एवं क्षतिकारी निर्यातों का प्रतिशत बढ़ेगा तथा यह भारतीय

मांग के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लेगा। इसके अतिरिक्त, यदि एकमात्र प्रत्युत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार एसजीपीएल के निर्यात व्यवहार और उसकी उत्पादन क्षमता के देखा जाता है, तो उससे प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एसजीपीएल की जात क्षमता 17,00,000 मी.टन है और जांच की अवधि के दौरान उसका उत्पादन केवल 3,25,367 मी.टन ही था। इससे अकेले एसजीपीएल के पास ही 13,74,633 मी.टन की बेशी क्षमता अनप्रयुक्त रह जाती है, जो भारत में कुल मांग की लगभग दोगुनी है। एसजीपीएल द्वारा इस उपलब्ध बेशी क्षमता का उपयोग भारत को न्यूनतम पाटित और ऊपर यथानिर्धारित विश्व को किए गए क्षतिकारी निर्यात कीमत पर किए जाने के लिए किया जा सकता है।

77. घरेलू उद्योग ने चीन में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है :

क्र. सं.	संयंत्र	उत्पादन क्षमता (मी. टन में)
1	जिंग जिंग पाइप कंपनी	18,00,000
2	बेन्क्सी बैताई पाइप कंपनी	6,00,000
3	लांगखाऊ फैनलिन पाइप कंपनी	2,50,000
4	सेंट गोबैन (जुझाऊ) पाइप कास्टिंग कंपनी लिमिटेड	17,00,000
5	डालियान कुंडा पाइप कंपनी (2)	1,50,000
6	जिन्वेंग चुन्चेन जिन्घुई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1,80,000
7	सन पाइपलाइन्स कंपनी लिमिटेड	1,50,000
8	जुझाऊ एवरब्राइट डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड	2,00,000
9	शान्दांग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड	3,00,000
10	रिझोऊ झुफु इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	2,00,000
11	क्विआनएन शि जिन्टांग आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड	90,000
12	शान्क्सी गुआघुआ कास्टिंग पाइप कंपनी लिमिटेड	3,00,000
13	यांगटांग डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड	4,00,000
14	जिन्जियांग ट्रेजरी डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लिमिटेड	2,00,000
15	कुल योग	65,20,000

78. घरेलू उद्योग द्वारा कुछ उत्पादकों/निर्यातकों की वेबसाइट्स से तथा कुछ अन्य उत्पादकों/निर्यातकों की भरोसेमंद वेबसाइट्स से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह देखा जाता है कि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। वे डक्टाइल आयरन पाइप्स का पूरे विश्व में निर्यात कर रहे हैं। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने न तो इस जानकारी का विरोध किया और न ही इसके संबंध में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार कोई ऐसी तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कराने में अक्षम रहे हैं जिसे वे बाद में बेशी क्षमताओं के मुद्दे का

निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी द्वारा विचार करने के लिए आवश्यक समझते हैं। अतः, यह निष्कर्ष निकालने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। यह क्षमता घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से बहुत अधिक है। इस तरह की भारी उत्पादन क्षमता और चीन से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए जाने वाले निर्यात की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

79. भारत को संभावित कीमत के संबंध में उपलब्ध रिकार्ड के तथ्यों तथा इस तथ्य पर कि चीन में भारी उत्पादन क्षमता है और यह कि चीन के किसी भी बड़े उत्पादक/निर्यातक तथा भारत के किसी भी आयातक ने इस जांच का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है, विचार करते हुए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत को पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु आएगी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होने की पूरी-पूरी संभावना है।

80. हितबद्ध पक्षकारों तथा प्रस्तुत किए गए तर्कों, प्रदान कराई गई जानकारी और किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों एवं पाटन तथा क्षति की संभावना का विश्लेषण सहित, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि :

- (i) विनिर्मित सामान्य मूल्य तथा भारत को संभावित निवल निर्यात कीमत स्पष्टतः यह इंगित करती है कि यदि वर्तमान शुल्क का प्रतिसंहरण कर देने की अनुमति दी जाती है तो चीन जन.गण. से पाटन की संभावना है।
- (ii) चीन जन.गण. से संभावित निर्यात कीमत स्पष्टतः संकेत करती है कि घरेलू उद्योग को कीमत अधोरदन के रूप में क्षति होने की संभावना है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

जांच की अवधि के दौरान संभावित कीमत अधोरदन

	अमरीकी डालर (प्रति मी.टन)
एनएसआर	***
उतराई मूल्य (संभावित)	***
संभावित अधोरदन मार्जिन	***
संभावित अधोरदन मार्जिन %	***
संभावित अधोरदन मार्जिन % रैंज	5-15

- (iii) चीन से संभावित निर्यात कीमत का घरेलू उद्योग को कीमत अधोबिक्रयण के रूप में होने वाली संभावित क्षति का स्पष्ट संकेत करती है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

जांच की अवधि के दौरान संभावित कीमत अधोबिक्रयण

	अमरीकी डालर (प्रति मी.टन)
गैर-क्षतिकारी कीमत	***
उतराई मूल्य (संभावित)	***
संभावित अधोबिक्रयण मार्जिन	***
संभावित अधोबिक्रयण मार्जिन %	***
संभावित अधोबिक्रयण मार्जिन % रेंज	0-10

- (iv) इसके अतिरिक्त उन्हीं आंकड़ों से भारत को संभावित कीमत ग्रहण करते हुए, क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है।
- (v) संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की उत्पादन क्षमता से संबंधित सूचना का विश्लेषण करने, जांच में चीन के बड़े उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने तथा भारत की घरेलू बाजार में कीमत आकर्षकता को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो चीन से भारत को पाटित आयातों एवं क्षतिकारी आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है और यह भी संभावना है कि इससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

अ. भारतीय उद्योग का हित

81. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य ऐसे पाटन का उपशमन करना होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा हो और इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति पुनः बहाल करना है जो सामान्यतः देश के हित में होती है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके दिनिर्मित किए गए उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार से पक्षपातरहित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर होगा, यह घरेलू उद्योग को हास से बचाएगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प प्रदान कराने में सहायता करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से होने वाले आयात को किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस कारण उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता इसकी आपूर्ति के दो या दो से अधिक स्रोत अभी भी बनाए रख सकते हैं।

ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

82. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुरूप विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से यह आधार बनाए रखने का अनुरोध किया गया कि निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन/रद्दो-बदल नहीं की जा सकती है।

ट.2 विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

83. केवल एसजीपीएल द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण किया गया है जो संक्षेप में निम्नलिखित है :

- क. इस कंपनी को सहयोगकर्ता निर्यातक कंपनी के रूप में माना जा सकता है;
- ख. इस कंपनी द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण कंपनी के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर किया जा सकता है;
- ग. 1100 मिमी. ब्यास से अधिक के ब्यास वाले डक्टाइल आयरन पाइप्स का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अवमोचन किया जा सकता है;
- घ. प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित नहीं किया कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो भारी मात्रा में पाटन होने की संभावना है;
- ङ. प्राधिकारी यह मान सकते हैं कि घरेलू उद्योग को आयातों के बिना भी पहले से ही क्षति हो रही है;
- च. प्राधिकारी यह धारणा कर सकते हैं कि सेंट गोबैन, चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को आयातों से क्षति होने की संभावना नहीं है;
- छ. सेंट गोबैन ने जांच शुरुआत नोटिस का भी प्रत्युत्तर दिया है और सभी संगत जानकारी उपलब्ध कराई है। सेंट गोबैन निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपना सहयोग प्रदान कराने के लिए पूर्णतया समर्पित है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण अनिवार्यतः विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) में उल्लिखित विधिक स्थिति के आधार पर प्राधिकारी से यह आधार अनुरक्षित रखने का अनुरोध किया जाता है कि वे निर्णायक समीक्षा जांच में उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन/रद्दो-बदल न करें। प्राधिकारी ने इन सभी

प्रस्तुतिकरणों और विधिक स्थिति का इस अधिसूचना में 'विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु' शीर्षक के अंतर्गत समुचित रूप से समाधान किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अन्य प्रस्तुतिकरणों तथा एसजीपीएल द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का समाधान भी इस जांच परिणाम के संगत भाग में किया गया है। प्राधिकारी पुनः उल्लेख करते हैं कि चूंकि एसजीपीएल चीन से विचाराधीन उत्पाद का एक बड़ा निर्यातक नहीं है इसलिए इस कंपनी द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने की स्थिति में, चीन से पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए उपयोगी नहीं है।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिश

85. घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान कराई गई सूचना तथा किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति की निरंतरता की संभावना के विश्लेषण सहित उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं और यह सिफारिश करते हैं कि :

- (i) वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद और सिफारिशों का दायरा सभी ब्यास के डकटाइल आयरन पाइप्स है।
- (ii) इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि यदि मौजूदा शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की अनुमति दी जाती है तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के भारत को पाटित एवं क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति भी पहुंचायी जा सकती है। भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग पर विचार करते हुए इन पाटित एवं क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है। यदि वर्तमान शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो चीन जन.गण. से पाटन किए जाने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाए जाने की पूरी संभावना है।
- (iii) अतः, प्राधिकारी सभी ब्यास के डकटाइल आयरन पाइप्स के संबद्ध देश से सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 103/2007-सीमाशुल्क के तहत उदगृहीत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

ड. अगली प्रक्रिया

86. केंद्रीय सरकार की इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से सृजित आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकती है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2013

(Final Findings)

Subject :—Sunset Review anti dumping investigation concerning imports of 'Ductile Iron Pipes' originating in or exported from China PR.

No. 15/1006/2012-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the anti-dumping duty was originally imposed on import of Ductile Iron Pipes originating in or exported from China PR vide Notification No. 103/2007-Customs dated 14th September, 2007.

A. Background of the case

1. Whereas the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or the AD Rules or the Anti Dumping Rules), had initiated the original investigation on the imports of Ductile Iron Pipes (hereinafter also referred to as DI Pipes or the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) vide Notification No. 14/14/2005-DGAD dated 24th February, 2006. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide its Notification No.14/14/2005-DGAD dated 23rd August, 2007. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 103/2007-Customs dated 14th September, 2007 on the imports of Ductile Iron Pipes originating in or exported from China PR.

2. Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duties imposed, shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review as to whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. M/s Electrosteel Castings Ltd., M/s Jindal Saw Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd, constituting the domestic industry (hereinafter also referred to as the Domestic Industry or the DI), submitted a petition before the Authority in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules to initiate sunset review investigation in respect of the anti dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No.103/2007-Customs dated 14th September, 2007. Having satisfied itself of the prima facie evidence to initiate the sunset review, the Authority, in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, initiated the sunset review vide Notification No. 15/1006/2012 dated 7th September, 2012 to examine as to whether cessation of the existing duty as notified vide Notification No.103/2007-Customs dated 14th September, 2007 would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. And whereas, the original antidumping duty has been extended by the Government of India up to 12th September, 2013 vide Notification No. 41/2012-Customs dated 13th September, 2012, in terms of Section 9(A)(5) of the Act.
4. The scope of the present sun set review investigation covers all aspects of the previous notifications.

B. Procedure followed in the Investigation

5. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of a petition from the Domestic Industry alleging dumping of the subject goods from the subject country before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 15/1006/2012 dated 7th September, 2012 in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules.
 - iii. The Authority forwarded copy of the Notification dated 7th September, 2012 to the Embassy of the subject country in India, known exporters, importers/users and the Domestic Industry and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter communicating the initiation of the investigation in accordance with the Rule 6(2) of the Rules.

iv. The Authority provided a copy of the petition as well as the exporter's questionnaire to the Embassy of the subject country in India and the following known exporters/manufacturers from the subject country in accordance with sub-rule (3) of Rule 6 supra with the request to provide relevant information to the Authority within the stipulated time:

1. Yongtong ductile cast iron pipe Co., Ltd
2. Benxi Beital Ductile Cast Iron Pipe Co., Ltd
3. Beital Iron and Steel Group Co., Ltd
4. Chengdu Jinfeng
5. Dalian Wantong Industrial Equipment Co., Ltd
6. Hydera Machinery Limited
7. Qian'an Shi Jintang Ductile Iron Pipes Co., Ltd.
8. Rizhao Zhufu Industry Co., Ltd.
9. Shandong Ductile Iron Pipes Co., Ltd
10. Shanghai Cast iron Pipe Plant
11. Shanxi Guanghua Cast Pipe Co., Ltd.
12. Shanxi Solid Industrial Co., Ltd
13. Xinjiang Treasury Ductile Iron Pipe Co., Ltd.
14. Xinxing Ductile Iron Pipes (Group) Co., Ltd.
15. Saint Gobain (Xuzhou) Pipe Casting Co., Ltd.

v. A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also provided to the known producers/exporters of the subject goods from the subject country and the Embassy of subject country in India with the request to provide relevant information to the Authority within the stipulated time.

vi. M/s Saint Gobain (Xuzhou) Pipelines Co. Ltd. filed their exporter's questionnaire response (hereinafter also referred as SGPL or the responding producer). No other exporter/producer from the subject country filed the questionnaires' response.

vii. Subsequently, at a much belated stage, i.e., subsequent to the public hearing, SGPL filed Part II of the questionnaire.

viii. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise other exporters/producers from that country who were not known to the Authority to respond to the initiation of investigation and the exporter's questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and the exporter's questionnaire which was sent to the known exporters was also sent to the Embassy of the subject country in India.

- ix. The importer's questionnaire was sent to the following known importers/users/user associations of the subject goods in India for necessary information within the prescribed time in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. Pratibha Industries Limited
 2. J V Gokal & Co. Pvt. Limited
 3. Gammon India Limited
 4. Larsen & Toubro Limited
 5. SPML India Limited
- x. None of the above mentioned importers/users/user associations or any other interested party responded to the questionnaire or the initiation notification.
- xi. The investigation was carried out for the period starting from 1st April 2011 to 31st March 2012 (12 months), i.e., the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period 2008-09, 2009-10, 2010-11 and the POI.
- xii. A copy of the non-confidential version of the petition was also provided to the other interested parties, wherever requested.
- xiii. The Authority kept a non-confidential version of the petition and other submissions presented by various interested parties from time to time in the form of a public file maintained by the Authority and kept the same open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
- xiv. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xv. The non-injurious price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of laid down guidelines under Annexure III of the AD Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvi. An Oral Hearing was held on 28th June, 2013 by the Designated Authority to invite comments from the interested parties. This was attended by the representatives of the Domestic Industry and SGPL. The Authority has considered the written submissions and rejoinders received from these interested parties on the issues raised by them in the Oral Hearing.

- xvii. On the spot verification of the data provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary by the Authority. No verification visit was carried out at the premises of SGPL as the Authority was of the view that the same was not necessary because the responding foreign producer SGPL had not exported the subject goods to India during the POI.
- xviii. The import data for the period of investigation and preceding three years was obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and considered to the extent found relevant to the investigation.
- xix. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 21.08.2013, so as to give them one more opportunity to submit comments and submissions, if any, on the contents and facts contained in the Disclosure Statement so as to examine these comments and submissions on their merits before the Final Finding could be issued. The post Disclosure Statement submissions received from the interested parties have been considered on merit, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- xx. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.
- xxi. The exchange rate adopted by the Authority in this investigation is 1USD=48.14 as per the relevant customs notification.

C. Product Under Consideration and the Like Article

Submissions by the Domestic Industry

- 6. The following preliminary submissions had been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and the like article:
 - (i) The present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration has to remain the same as that of the original investigation in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules. This is also the consistent practice of the Authority.
 - (ii) There is no difference in subject goods produced by the domestic industry and the subject goods produced in and exported from China PR and the subject goods are like articles in terms of the Rule 2(b) of the Rules.

- (C) There is no material difference in the production process employed by the Chinese producers and the Indian producers of the subject goods.

Submissions by the responding foreign producer

The only responding foreign producer, SGPL, China PR, had made the following preliminary submissions:

- (i) There is no manufacturing of DI Pipes of above 1.2 meter diameters in India and accordingly, all such pipes of higher diameter ought to be excluded from the purview of anti-dumping duties.
- (ii) The Authority is required to examine all the factors in the sunset review investigation including the product scope.
- (iii) Foreign producers producing higher diameters pipes are unable to export to India because of existing anti-dumping duties.

Examination by the Authority

In the original investigation, the product under consideration was defined as under:

5. *"The product under consideration is Ductile Iron Spun Pipe as defined under clause 3.1 and 3.2 of International Standard, ISO 2531 (for water and gas) and ISO:7186 (for sewage applications). These are often also described as Spheroidal Graphite Iron Pipes or Ductile Cast Iron Pipes or Ductile Iron Spun Pipes. These are classifiable within 73030030 and 73030090 of the Customs Tariff Act.*
6. *DI Pipes performs the function of transporting liquid object at long distances at high pressure. It is primarily used for transporting water or sewerage disposal and gas, transmission of domestic and industrial effluent, fire-fighting systems on shore and off-shore. The various applications of DI Pipes are:*
 1. *Transmission of raw, potable and sea water at high pressures.*
 2. *Distribution of potable water and gas.*
 3. *Disposal of domestic and industrial effluent.*
 4. *Fire-fighting systems on shore and off shore".*

Ductile Iron Pipes are commonly known as DI Pipes-Ductile Iron Spun Pipe- as defined under clause 3.1 and 3.2 of International Standard, ISO 2531 (for water and gas) and ISO: 7186 (for sewage applications)-classifiable within 73030030 and 73030090 of the Customs Tariff Act, 1975. These are often also described as Spheroidal Graphite Iron Pipes or Ductile Cast Iron Pipes or Ductile Iron Spun Pipes. DI Pipes perform the function of transporting liquid object at long distances at high pressure. These are primarily used for transporting water or sewerage disposal and gas, transmission of domestic and industrial effluent, fire-fighting systems on shore and off-shore. The various applications of DI Pipes are transmission of raw, potable and sea water at high pressures, distribution of potable water and gas, disposal of domestic and industrial effluent and fire-fighting systems on shore and off shore.

10. The Authority noted that with regard to the Product Under Consideration the responding foreign producer had submitted that since there is no manufacturing of DI Pipes of 1.2 meter and above diameters in India, all such pipes of higher diameter ought to be excluded from the purview of anti-dumping duties. The domestic industry, on the other hand, had submitted that the present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration legally has to remain the same as that of the original investigation in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules and that this is also the consistent practice of the Authority.
11. The Authority had examined these preliminary counter arguments on the product under consideration on the basis of submissions made by the responding producer and the domestic industry to the Authority before issuance of the Disclosure Statement and other information and records available to the Authority at that time and in accordance with that the Authority had noted that (i) the responding interested party from China PR, SGPL, has not exported DI Pipes (including DI Pipes of diameter 1.2 meter and above) to India in the POI, post POI as well as the injury period; (ii) no importer or any other opposing interested party has imported DI Pipes from any source and responded in the investigation at all- neither by way of importer questionnaire and/or any other submissions etc, including any request for exclusion of DI Pipes of any particular diameter; (iii) at the same time, during the course of the investigation the Authority also noted that the domestic industry is not manufacturing DI Pipes of 1.2 meter and above diameters; and (iv) in the final findings in the original investigation as well as the corresponding customs notification, the product was described as "*Ductile Iron Pipes*", falling under customs tariff items 73030030 and 73030090 which do not limit the scope of the Ductile Iron Pipes to any particular diameter. In view of the aforesaid, the Authority in the Disclosure Statement issued in this investigation had proposed to conclude that the contention of SGPL is misplaced as the present investigation is only a sunset review investigation and in a sunset review, in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the scope of the product under consideration will remain the same as that in the original investigation. In view of the aforesaid, the Authority had proposed to determine that the scope of the Product under Consideration in the present investigation remains the same as that of the original investigation, i.e., Ductile Iron Pipes of all Diameters falling under customs tariff items 73030030 and 73030090.
12. The Authority had issued a Disclosure Statement to invite further comments on the contents contained therein from the interested parties. The Authority notes that in response to Disclosure Statement, SGPL has provided the following arguments to elaborate their point of view to exclude DI Pipes above 1100mm diameter:
- (i) Even though it is an admitted position that the petitioner domestic industry cannot produce Ductile Iron Pipe above 1100 mm dia, Saint Gobain submits that production of Ductile Iron Pipe above 1100 mm dia is not possible for the domestic industry for the reason that the domestic industry lacks necessary manufacturing facilities in the form of required type of plant and equipment. Production of Ductile

Iron Pipe above 1100 mm dia requires deployment of the plant & machineries of requisite specifications. The process of manufacture of Ductile Iron pipe consists of a centrifugal casting machine where the liquid metal is poured into moulds which is spun at high speeds to produce pipes of required diameter and length. The pipes are then extracted from the mould and sent to the annealing furnace where it is heat treated. It is then coated on both inside and outside on special finishing lines which also have inspection devices to check the leak proof nature of the pipes. The casting machine, annealing furnace and finishing lines are all built for certain specific range of diameters and it is not feasible to use the set up flexibly to make pipes outside of this design range. The largest pipe that the Indian industry can produce with its current facilities is 1.1 meters. If they want to produce pipes of larger size, they need to invest in larger casting machines, larger annealing furnaces and larger finishing lines which in effect mean a totally new plant. The current plant & machineries cannot handle this process required for producing pipes above 1100 mm dia. This requires large capital expenditure not only for the equipment but also for the building and utilities to support the machines. This project will also take long time for execution. No customer can order the pipes and wait for the new plant to be set up and pipes made.

(ii) It is a misplaced legal position that the Authority cannot review scope of product under consideration in a sunset review. The Designated Authority has in the past reviewed the scope of product under consideration during sunset review. In the matter of Sunset Review investigation of anti dumping duty imposed on imports of PVC Paste Resin, the Authority not only reviewed the scope of product under consideration but also exempted one product type from the scope of the product under consideration. In this matter, the disclosure statement issued before CESTAT order included PVC Paste/Emulsion Resin with K value below 60 and with K value above 78 but post CESTAT order, the interested parties sought exclusion of PVC Paste/Emulsion Resin with K Value above 78 and after elaborate investigations, the Authority excluded PVC paste resin with K value below 60 and included PVC paste resin with K value above 78.

13. The Authority further notes that in response to Disclosure Statement, the domestic industry has maintained that they are currently manufacturing DI Pipes up to 1200mm diameters and also provided the following arguments to elaborate their point of view as to why DI Pipes above 1200mm diameter should not be excluded:

(i) The present investigation is only a sunset review investigation in terms of Section 9A (5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules where the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation. Seeking a review of the Product under Consideration in a sunset review is not only ill-advised but also illegal.

(ii) As regard the observation of the Authority that Domestic Industry is not manufacturing DI Pipes of 1.2 meter and above diameters in India, it is submitted that

any part of the Final Findings which is not specifically mentioned in the review initiation notification cannot be addressed. This would be against the provisions of the anti-dumping laws. The initiation notification in the present sunset review investigation itself restricts the scope and it is neither open nor permissible to address issues which do not form part of the initiation notification. Amending the Product under Consideration would amount to carrying out changes which were not even a part of the initiation notice. Domestic Industry would also like to submit that this very issue was in existence during the initial investigation in 2007 wherein it was mentioned that in India, DI Pipes are made in several sizes varying from 80mm to 1100mm diameters. Large sizes of pipes can also be made. No comments and/or objection was recorded/observed on this statement that "Large sizes of pipes can also be made" during the initial investigation in 2007. No appeal was also filed against the Final Findings by any of the interested parties.

(iii) Further, presently there is no demand of DI pipes exceeding 1200 mm diameter in India. To the best of the information of the Domestic Industry, no tenders of DI pipes exceeding 1200mm diameter have been floated so far in the Indian market. Further, the domestic industry understands that no imports of even higher dias has taken place in the Period of Investigation. Currently, the Domestic Industry has been producing DI pipes up to 1200 mm diameter in India because so far there has been no demand for higher dias in India. It may be noted that for higher size DI pipe, liquid metal and various other facilities are common and some additional investment is required only in spinning machine and annealing furnace. Production flow chart submitted indicates the stage where updation is required.

(iv) It is reiterated that the Indian industry is in the advanced stage of setting up a Greenfield Steel Project at Bokaro, Jharkhand. This project includes a plant for manufacturing DI pipes in sizes above 1200 mm also. It is important to note that substantial investments have already been made. Out of the estimated project cost of Rs.400 crores for this DI pipe plant, Rs 300 crores has been already invested. This clearly proves that any such exclusion would not only be contrary to law but also detriment to the interests of the Domestic Industry.

(v) It may be recalled that the principles set out by the Authority in the case of SDH Equipment [Final Findings No. 14/2/2009-DGAD dated 19.10.2010] are fully applicable in the facts of this case. In the said case (even though it was a fresh investigation), the Authority concluded that no product can be excluded unless it is exported to India during the investigation period in order to prove that domestic industry is not capable of supplying the said product. It also held that exclusions cannot be sought if there have been substantial investigations to produce those products by the Domestic Industry during the relevant period. From this case, it is clear that even in the fresh investigation, the Authority has not excluded the product on the grounds that the product has not been exported in the country by the exporters

and on the premise that significant investments were made by the Domestic Industry to develop the product.

14. The Authority has examined all these facts and post Disclosure Statement submissions and past precedence with respect to changing the scope of the product under consideration in a sunset review investigation and concludes the following:

(i) As regards the reference of SGPL and the domestic industry to certain previous investigations dealing with the change in the product scope by the Authority, the Authority is of the view that an investigation is conducted on the individual facts and merits of each case which may differ. Still, as regards the contention of the responding exporter that in the matter of PVC Paste/Emulsion Resin referred above (Sunset Review Investigation of anti dumping duty imposed on imports of PVC Paste Resin originating in or exported from European Union-Final Findings No 15/27/2008-DGAD dated 4th April, 2013), in which the product scope was changed/curtailed by the Authority in a sunset review, the Authority notes that the facts in that case and the present case are different. In the above referred case, the Authority had excluded certain product type not because the domestic industry was not manufacturing that certain type of product but because the Authority had already excluded the concerned product type in a parallel investigation (Anti dumping investigation concerning imports of PVC Paste Resin originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand).

(ii) As regards the contention of the responding exporter that the production of Ductile Iron Pipes above 1100 mm dia is not possible for the domestic industry for the reason that the domestic industry lacks necessary manufacturing facilities in the form of required type of plant and equipment, the Authority notes that the issue that Domestic Industry manufactures DI Pipes up to 1100 mm dia only was in existence during the original investigation in 2007 as well but no comments and/or objection were recorded/observed on the statement that "Large sizes of pipes can also be made." The Authority notes that in the present sunset review investigation, though admittedly the Domestic Industry is manufacturing DI Pipes up to 1100mm dia only and SGPL has raised this issue, these are also the facts that (i) in the absence of demand, neither the responding interested party from China PR, SGPL, has exported DI Pipes (including DI Pipes of diameter 1.2 meter and above) to India in the POI, post POI as well as the injury period nor the domestic industry has manufactured higher dia pipes; and (ii) no importer or any other opposing interested party has imported DI Pipes from any source and responded in the investigation at all- neither by way of importer questionnaire nor by any other submissions etc, including any request for exclusion of DI Pipes of any particular diameter.

15. After careful consideration of the above facts and submissions as well as the past precedence, the Authority maintains its stand that the scope of the product under consideration remains Ductile Iron Pipes of all diameters falling under customs tariff items 73030030 and 73030090.

16. No argument has been raised by any interested party on the issue of “like article”. In view of above, the Authority holds that the DI pipes manufactured by the domestic industry and those produced in China PR are “like articles” in terms of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

D. Scope of the Domestic Industry and Standing

Submissions by the Domestic Industry .

17. M/s Electrosteel Castings Ltd., M/s Jindal Saw Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd, constituting the domestic industry. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- (i) The applicants' share of production of subject goods constitutes 72% of the total Indian production which constitutes a major proportion of the total domestic production in the country. Further, they have not imported the subject goods from the subject country and hence they constitute the eligible domestic industry in terms of Rule 2(b).
 - (ii) As regards the issue of “Standing”, it is submitted that the test of “Standing” is not applicable in any proceeding under Section 9A(5) and, therefore, irrelevant. Nevertheless, they meet with all the criteria of “Standing” in terms of Rule 5.

Submissions by the responding foreign producer

18. SGPL is not disputing the share of the petitioners in the total domestic production, but raises certain issues regarding the computation of the total demand in the country. They have submitted when the share of Domestic Industry in production is 72%, they could not have computed the total demand based only on their sales figures.

Examination by the Authority

19. The Authority notes that no relevant submission has been made by any interested party with regard to the status of the domestic industry to the present case. The Authority, therefore, has examined the merits of the information of the applicants, namely, M/s Electrosteel Castings Ltd., M/s Jindal Saw Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd., and considers them as eligible domestic industry for the purpose of the present sunset review investigation within the meaning of the Rules.

E. Issues relating to Confidentiality

Submissions made by the responding foreign producer

20. The following are the submissions made by the responding foreign producer concerning confidentiality:

- (i) Excessive confidentiality claimed by the domestic industry and allowed by the Authority.
- (ii) Consolidated information of domestic industry should not be allowed to be kept confidential.
- (iii) Information available in the public domain should not be allowed to be kept confidential.

Submissions by the Domestic Industry

21. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to the issue of confidentiality:
- (i) That the petitioner has claimed confidentiality in accordance with the provisions of the law and the Trade Notice issued by the Authority in this regard. The claim of confidentiality has been made with proper justification and so permitted by the Authority.
 - (ii) On the contrary, the responding foreign producer has itself claimed confidentiality without providing statement of confidentiality which is a prerequisite under the Rules and the procedure. No claim of confidentiality can be allowed unless and until such claim is supported by proper justification. The foreign producer has claimed confidentiality even on its product brochure and product catalogues which cannot be permitted in terms of the Rules and the Trade Notice issued in this regard. In any case, since the foreign producer has failed to fulfill its obligations under the Rules, their claim for confidentiality and all the information submitted by them ought to be rejected.
 - (iii) SGPL has not disclosed that one of their related companies is also engaged in the production of subject goods in China PR and, to that extent, has withheld the information even from the Authority.
 - (iv) In support of its claim to confidentiality, the Domestic Industry argues that even the consolidated injury information cannot be disclosed considering that out of three companies constituting domestic industry, two companies are related to each other. Disclosure of information in the non-confidential version would make it possible for competitors to infer each other's commercially

sensitive information. Furthermore, disclosure of price related information such as profit, return on capital employed, cash flow, cost of production, selling price, etc. would cause serious prejudice to the interest of the domestic industry.

Examination by the Authority

22. The Authority made available to the interested parties the public file containing non-confidential version of evidences / information submitted by the interested parties for inspection, upon request, as per Rule 6(7). The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied with regard to the claim on confidentiality, the same has been allowed in accordance with the rules and the standard practices of the Authority.

F. Miscellaneous Submissions

Other submissions by the responding foreign producer

23. The responding foreign producer SGPL has submitted that adequate protection of anti dumping duty has been given to Domestic Industry for 5 years during which the Domestic Industry should have improved its position.

Other submissions by the Domestic Industry

24. The responding foreign producer SGPL at many times during the course of investigation attempted to mislead the Authority by addressing themselves as exporter of the subject goods at some places and foreign produces at other places. In fact, they had not been able to clarify as to why they are opposing the duties if their ultimate plan is to set up production facility in India.
25. During the public hearing the responding foreign producer SGPL has accepted that they have not submitted Part II of exporter questionnaire. Domestic Industry is unable to appreciate how in the written submissions they can claim they have submitted all the information to the Authority. It is the consistent practice of the DGAD not to accept any response by any party after the public hearing. It is further submitted that in several cases the Authority rejected the information because the information was filed first time after the public hearing. Acceptance of responses at this belated stage of the investigation would be against all the principles of pleadings and natural justice. As regards the contention of SGPL that neither the Designated Authority nor the Domestic Industry pointed out the deficiency for such a long time, it is submitted that such an approach is a feeble and mischievous attempt by the party to shift its burden on other parties. Further, this is not a case of deficient information but complete failure to file the prescribed format itself. It is clear that despite the assistance of

professionals, the said party has not fulfilled its legal responsibility. This surely is not a case of error, but a deliberate attempt to withhold the information to mislead the Authority.

Examination by the Authority

26. The Authority notes that the purpose of a sunset review is to examine as to whether there is any likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event the anti-dumping duties are not extended and for this purpose all the relevant information is to be examined by the Authority.
27. The Authority notes that the responding foreign producer has not provided the relevant Part II questionnaire response. The Authority also notes that, admittedly, the responding exporter is not the major exporter of the product under consideration from China and, therefore, in any case their questionnaire response is not useful in deciding likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duty. Therefore, their questionnaire response cannot be considered as sufficient for the purpose of the present investigation. Once the investigation has been initiated and the Authority has sent notices to all the interested parties to provide the relevant information, the onus of submitting the information in all the prescribed formats is on the interested parties. The major Chinese companies have not cooperated with the Designated Authority with questionnaire response and, therefore, the Authority is required to determine likelihood of dumping and injury based on best available information. Further, since there is no export from China during the current period, the Authority is required to determine likelihood of injury on the basis of cumulative exports from China. It is also noted that since the purpose of the present review is to determine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duty, in a situation like the present where there were no exports from China to India, the likelihood of dumping and injury is required to be determined based on extent of dumped and injurious imports from China. Thus, individual questionnaire response from China in a sunset review case where there are no exports is of limited relevance.

G. Assessment of Dumping – Methodology and Parameters

Dumping Margin and Likelihood of Dumping

Normal Value

Submissions made by the Domestic Industry

28. The Domestic Industry has made the following submissions:
 - (i) Normal value for China PR has to be determined in terms of the provisions for non-market economy countries.
 - (ii) After the determination of the fact that Chinese producers are not entitled for market economy treatment, the Authority shall follow Para 7 of Annexure I of

the AD Rules for the determination of Normal Value. Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. In order to arrive at Normal Value on this basis, the Authority shall require complete and exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Anti Dumping Agreement are also relevant in this respect. Petitioners have not been able to procure such information from a producer in the market economy third country.

- (iii) In the original investigation, the Authority had not granted market economy treatment to any of the exporters from China and determined the Normal Value in China on the basis of the constructed Normal Value based on the estimated cost of production of the subject goods in China with reasonable profit in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. The petitioners request the Authority to consider the same methodology to calculate the Normal Value for China PR in the current investigation.
- (iv) The proposed Normal Value in China has been computed on the basis of cost of production in India, duly adjusted. The raw material cost for DI Pipes has been calculated on the basis of the weighted cost of raw material of the domestic industry as the same is indicative of the international prices.
- (v) As regards the submission of the respondent that their cost of production is not lower than that of the domestic industry in India, the domestic industry submits that if the contention of the respondent is true then it would only lead to a higher dumping margin. With the high level of likely dumping margin, it is almost certain that in the event duties are removed, there is every chance that exporters from China would again start dumping of the subject goods in India.

Submissions by the responding foreign producer

29. Following submissions have been made by sole responding foreign producer SGPL:

- (i) The petitioner has claimed significantly higher normal value in an attempt to establish dumping when none exists.
- (ii) The petitioner has considered "weighted average cost of raw material for the Domestic Industry" which is clearly against established practice. The Designated

Authority considers international prices for raw material and not the consumption price of the Domestic Industry. This is more so in the present case when there are significant imports of one of the key raw materials, i.e., iron ore and other raw material involved in the production of the product.

- (iii) The Authority has not followed the consistent practice of considering the lowest normated cost and lowest NIP for constructing normal value.
- (iv) The petitioner has claimed China as non market economy country and further, claimed that the normal value is required to be constructed based on Para 7 of annexure 1. Therefore, the prices prevailing in China are totally irrelevant to the petitioner and yet the petitioner has proceeded by considering Chinese cost.
- (v) The erroneous and inflated working of the normal value becomes very obvious when compared with the prices at which Domestic Industry is exporting to countries like Qatar, Singapore, Spain or even the prevailing market prices.

Examination by the Authority

- 30. As a part of the proceedings in this investigation, the Authority had sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country advising them to provide information in the form and manner prescribed. As mentioned above, there has been no response to the questionnaire nor has there been any submission by the any of the major Chinese producers/exporters except SGPL. Only SGPL, who incidentally does not account for the major share of exports from China to other countries, has responded and that too partially after the oral hearing. It is also noted that SGPL has not exported the subject goods to India during the POI. The major Chinese companies have not cooperated with the Authority with questionnaire response and, therefore, the Authority is required to determine likelihood of dumping and injury based on cumulative exports from China. It is also noted that since the purpose of the present review is to determine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duty, in a situation like the present where there were no exports from China, the likelihood of dumping and injury is required to be determined based on extent of dumped and injurious imports from China. Thus, individual questionnaire response from China in a sunset review case where there are no exports is of limited relevance.
- 31. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non market economy country in the anti-dumping investigations by India subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters/producers in terms of the AD Rules.

32. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s)/producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/producers of the subject goods from China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:
- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology, labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
33. It is noted that none of the Chinese exporters/producers, except SGPL, has responded to the prescribed questionnaires nor submitted complete questionnaire responses. SGPL has submitted part information. However, the company is not a major exporter of the product under consideration from China. In the absence of cooperation from the Chinese exporters/producers, it would not be appropriate to take cognizance of the part information supplied by the sole respondent, namely, SGPL. The Authority, therefore, determines the normal value in accordance with para 7 of Annexure 1 to the Rules.
34. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due

account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”.

35. As regards questionnaire response filed by SGPL and market economy treatment claimed by them, the authority notes that the likelihood of dumping and injury in the present case is based on total exports from China and the same cannot be based on exports by individual Chinese company. Therefore, the Authority has not determined normal value for SGPL. Claim of market economy treatment by SGPL becomes relevant only if the Authority decides normal value for SGPL. In the absence of any exports to India, the Authority has not determined individual dumping margin for Chinese exporters. Market economy treatment and normal value claimed by SGPL is therefore of no relevance in the present case in the absence of questionnaire response from major Chinese exporters. The AD Rules remaining un-rebutted, the Authority has proposed to determine the constructed Normal Value in accordance with para 7, Annexure I of the AD Rules for the reasons mentioned earlier. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are stipulated in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority determines the Normal value by adopting the method “any other reasonable basis”.
36. The Authority has relied on the international prices of major raw material along with the consumption norms, conversion cost and SGA of the most efficient domestic producer. Profit @ 5% on the cost of production has been added to arrive at the constructed normal value. By adopting this method, the constructed normal value is determined as US\$ *** per MT.

Export Price

37. The Authority notes that there are no exports of the subject goods to India from the subject country in the entire injury investigation period including the POI and the post POI. In the absence of exports to India by any of the Chinese exporters including the responding producer/exporter SGPL from China, the Authority has not been able to determine the ex-factory export price for the POI and the post POI period.

Dumping Margin

38. Since there are no exports of the subject goods to India from the subject country in the entire injury investigation period including the POI, the Authority has not been able to determine the ex-factory export price and the dumping margin for the POI and the post POI period.

H. Assessment of Injury and Examination of Causal Link

Assessment of Injury

Submissions made by the Domestic Industry

39. Domestic Industry has submitted as follows:

- (i) Since there have been no imports of the subject goods either during the Period of Investigation or the injury investigation period, no injury analysis can possibly be made of current injury. In any case, the analysis of current injury recedes into insignificance in case of a sunset review particularly when there are no imports.
- (ii) Domestic Industry further submits that the mandate of the law for the Authority is only to carry out likelihood analysis as envisaged in Section 9A (5). Further, the Domestic Industry has been able to collect data of exports by the Chinese exporter to other countries during this period. There is sufficient indication that if the export price to other countries is taken as an estimate of the likely export price to India (once the anti-dumping duties are removed), it would be clear that the Chinese exports will injure the Domestic Industry. The price undercutting as well as price underselling analysis would reveal that if the duties are not extended, the injury to the domestic industry is imminent.

Submissions made by the responding foreign producer

40. SGPL has made the following submissions:

- (i) Domestic Industry is suffering injury because of the internal competition and some other factors such as non-availability of coal, delay in projects etc. Domestic Industry has straightaway jumped to likelihood without commenting about the current status of injury to them. It is further submitted that the current injury cannot be attributed to import as there are no imports of the subject goods in India.
- (ii) SGPL further submits that if the Domestic Industry matches the prices of exports from China, their profitability will increase. Further, SGPL submits that cessation of anti-dumping duties cannot lead to deterioration of profitability as their likely landed price of imports shall be higher than that of the Domestic Industry prices.
- (iii) Future imports of SGPL will not lead to price suppression in the market. Further, Domestic Industry will never reach the non-injurious price because of huge surplus capacity and cut-throat competition in the market.

Examination by the Authority

41. The Authority notes that there have been no imports of the subject goods either during the Period of Investigation or the injury investigation period in this sunset review investigation. The Authority's emphasis, therefore, is on analysing the likelihood of dumping and injury though the Authority analyzed the factors in relation to the current injury as well. Further, the Authority notes that SGPL has not exported the subject goods to India during the entire injury investigation period and also not provided the relevant data as required by the Authority in the stipulated timelines.

Volume Effect and Price Effect of the dumped imports

42. The Authority notes as per the Rules, the Authority is required to do the analysis of the volume effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry to determine price undercutting/price underselling/price suppression/price depression.

Economic parameters relating to the domestic industry

43. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows:-

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments”

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

44. The volume of domestic production and effects of dumped imports on the domestic operation of the domestic industry cannot be examined in terms of total production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry as there are no imports of the subject goods during the entire injury investigation period. However, the Authority notes capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry as under:-

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	April 2011 to March 2012 (POI)
Capacity-DI	MT	760000	760000	760000	805000

Production-DI	MT	626955	661231	668004	641504
Production-Others	MT	47401	67627	128309	250000
Capacity Utilization-DI	%	82%	87%	88%	80%
Domestic Sales-DI	MT	526608	554930	532699	459512
Domestic Sales-Others	MT	31518	67527	107701	205116
Imports from all Sources	MT	Nil	Nil	Nil	Nil
Export Sales-DI	MT	***	***	***	***
Total Demand (MT)	MT	558126	622456	640400	664628

45. The Authority notes that:-

i. The Domestic Industry increased its capacity to meet the increasing demand of the product in India. The production of domestic industry has also increased in the POI as compared to the base year, i.e., 2008-09.

ii. Capacity utilization of the domestic industry during the POI has declined as compared to the base year as well as the previous year.

iii. The Authority further notes that the domestic sale of the domestic industry has also declined during the POI as compared to the base year as well as the previous year.

iv. It is also seen that the production of other producers in India has increased in the POI as compared to the base year.

Profits, return on investment and cash profit

46. The profits, cash profit and return on investments earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as under: -

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Per unit profit/loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	288	173	-29
Profit/loss on domestic sales	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	303	175	-25
Profit before interest & tax	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	217	141	14

Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	249	159	2
Return on Investments	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	255	211	15

49. The Authority notes that:

i. Domestic industry's profitability has improved in 2009-10 and then declined in 2010-11 and then further declined in the POI.

ii. Similar trend is observed in case of cash profit and return on investment also.

Employment, wages and productivity

50. The number of employees employed by the domestic industry, wages paid and its productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend		100	100	109	84
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		100	113	133	128
Productivity per employee	MT/Nos.	***	***	***	***
Trend		100	105	98	121
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***

51. The Authority notes that:

i. Productivity per employee has increased in the POI as compared to the base year and productivity per day in POI has increased as compared to the base year. However the same has decreased as compared to the previous year.

ii. Wages paid to the employees increased till in 2010-11 and then declined in POI. However, overall wages paid increased in the POI as compared to the base year.

Inventories

52. Inventory position of the domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend		100	122	181	291

53. As noted the average inventory of the domestic industry increased during the entire investigation period.

Magnitude of Dumping Margin

52. The Authority notes that dumping margin from the subject country cannot be examined as there are no imports of the subject goods during the entire injury period. However, the likelihood of dumping has been analysed in the latter part of this Final Finding.

Ability to raise capital

53. The condition of the Domestic Industry will become worse once the anti-dumping duties in force are withdrawn as this will provide a stimulus to the manufacturers and exporters of the subject goods from the subject country to dump the subject goods at dumped prices in the domestic market. Therefore, Domestic Industry will face serious problem to raise capital from the market or from financial institutions.
54. The petitioning companies are multi-product companies. However, the present analysis has been done only for the Product under Consideration and the performance of other products does not have any bearing on the performance of the Product under Consideration.

Growth

55. The Authority notes from the table below that the growth of the domestic industry in respect of production, sales, market share, demand, profitability and ROC had declined during the injury period.

Particulars	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Production (%)	-	5.5%	1.0%	-4.0%
Sales (%)	-	5.4%	-4.0%	-13.7%
Market Share(%)	-	-5.5%	-6.7%	-16.9%
Demand(%)	-	11.5%	2.9%	3.8%
Profitability(Rs in lakh%)	-	203.2%	-42.2%	-114.3%
ROC(%)	-	154.8%	-17.0%	92.7%

Examination of Causal Link:**Submissions made by the Domestic Industry**

56. The domestic industry submits that:

- (i) It is a settled position of law that causal link analysis is not mandatorily required to be done in sunset review investigations. In this connection, the domestic industry invites the attention of the Authority to the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005):

"118. We therefore agree with Mexico that this fundamental principle is expressed in Article VI of the GATT 1994 and in various provisions of the Anti-Dumping Agreement. The United States does not question this principle per se. However, this does not mean that a causal link between dumping and injury is required to be established anew in a "review" conducted under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement. This is because the "review"

3805 61/13-9

contemplated in Article 11.3 is a "distinct" process with a "different" purpose from the original investigation."

119. The Appellate Body has underlined that "the nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature of the determination to be made in an original investigation", and that "[t]he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes."

X. Findings and Conclusions

219. for the reasons set forth in this Report, the Appellate Body:

(a) in relation to causation:

(i) finds that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely injury, as a matter of legal obligation, in a sunset review determination under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and that, therefore, the USITC was not required to demonstrate such a link in making its likelihood-of-injury determination in the sunset review at issue in this dispute;"

- (ii) It is further submitted that there are good technical and logical reasons for not applying the requirement of causal link in a sunset review case. If duties can be extended even if there are no imports, the question of carrying out the causation analysis does not arise. Further, the test for extension of the period of duties under Section 9A(5) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Submissions made by the responding foreign producer

57. The Authority notes that the foreign producer has claimed that domestic industry has not provided information on causal link as it is not mandatory in the sunset review cases. This approach is contradictory to the established practice of the DGAD. In view of this, the responding interested party requests the Authority to kindly follow the consistent practice followed by the DGAD in every case. Further, domestic industry is facing material injury despite no imports from the subject countries.

Examination by the Authority

58. Annexure 2 to the Rules provides as follows with regard to Causal Link:

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the Designated Authority. The Designated Authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

59. As far as the analysis of injury caused by the other factors is concerned, the Authority notes as under:

Volume and value of imports not sold at dumping prices:

60. There are no imports of the subject goods from the subject country in the entire injury period. Further, there are no imports from other countries also. Therefore, volume and value of imports and its impact on the domestic industry cannot be analysed.

Contraction in demand:

61. Demand of the product under consideration has not registered any negative growth. Instead, it has increased and shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to the injury to the domestic industry. Further, there is no reason to believe that demand is likely to decline.

Changes in the patterns of consumption:

62. The DI pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

63. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry. It is also seen that the production of other producers in India has increased in the POI as compared to the base year. It indicates that the decline in the

production of the domestic industry seems to be due to the competition from the other domestic producers.

Developments in technology:

64. Technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in the coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

Export performance:

65. The petitioning companies export the product under consideration. However, only information relating to domestic sales has been taken into consideration for assessment of injury.

1. Likely Export Price, Likelihood of Continuation/Recurrence of Dumping and Likelihood of Continuation/Recurrence of Injury

Submissions made by the domestic industry

66. The following submissions have been made by the domestic industry regarding the likely export price, likelihood of continuation/recurrence of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury:

- (i) The present duty is to be continued to protect the interest of domestic industry from the adverse effect of dumping of the subject goods from the subject country. Since there have been no exports of the subject goods during the Period of Investigation or in the preceding years, the Domestic Industry has submitted that the Authority needs to determine the likely export price to India on the basis of the export prices of the said goods from China to other appropriate third countries. It is submitted that export price to Saudi Arabia can be considered as the most appropriate as China exports 32% of D I Pipes to Saudi Arabia and the significance of water distribution is similar in the two countries. Similarly, the Domestic Industry had also considered the prices to Pakistan and Bangladesh for likely export price to India. It is submitted that the prices to these countries, which are geographically in the same region, are also comparable even though the volumes to these countries are small. Without prejudice, it is submitted by the Domestic Industry that the proposition of the foreign producer to consider weighted average export price to the rest of the world as an estimate of the likely export price to India, does not have any legal or economic justification. The anti-dumping rules and jurisprudence provides enough indication that "appropriateness" is the criterion to be used when it comes to third country prices.

- (ii) The said foreign producer has accepted that they are not major exporters from China. Therefore, their submissions/information cannot be of any significance as it cannot be considered as representative data from China to determine the likely export price to India.
- (iii) Calculation of export price has been done strictly as per the consistent practice of the DGAD. Further, for reaching landed value, the domestic industry has added ocean freight, insurance, landing charges and custom duty to the FOB value. The same ocean freight and insurance is deducted to arrive at the ex-factory price. Therefore, there are no errors in the methodology used by the domestic industry to determine ex-factory price of subject goods in China.
- (iv) China is having huge production capacity to meet the entire domestic demand in India. Moreover, China had made substantial capacity addition. The capacity addition itself is more than the total production capacity of the Domestic Industry. Furthermore, huge capacity additions are in the pipeline.
- (v) Export prices to other countries clearly indicate the likely behavior of the exporters from China. Further, the sole respondent has admitted the fact that they would be selling the subject goods into the Indian market at prices lower than the domestic prices in India in order to capture the market. That being the case, the increased level of price undercutting is imminent.
- (vi) Dumping margin calculated on the basis of the likely export price is in the range of 50%-60%. In such a situation, withdrawal of anti-dumping duties will only worsen the situation of the Domestic Industry as it will encourage free flow of dumped imports which will definitely have an adverse impact on the domestic selling price, market share and ultimately on profits of the domestic industry.
- (vii) With the huge surplus capacities available in China and the low price at which the subject goods are being supplied to other countries, it is clear that the domestic producers in India will have no option but to match such Chinese prices. According to the export statistics of China, the FOB price to Saudi Arabia is Rs. 36190 per MT. Adding the other elements of landed value, namely, freight, handling charges and basic customs duties, the landed value works out to be 40472 Per MT. The said estimated landed value has a significant price underselling of 36% and price undercutting of 11%.
- (viii) Similar position would emerge even if the analysis is carried out on the basis of the export prices to countries like Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka.
- (ix) If the goods are sold at the likely landed value, it is imminent that the Domestic Industry will suffer huge losses on their sales. The likelihood of

recurrence of dumping and continuation of injury and the injurious effect on the prices of the domestic industry is, therefore, imminent.

- (x) Domestic Industry reiterates that the Chinese products are not competitive unless and until they indulge in dumping practices. Further, the present level of anti-dumping is only about 15% of CIF value, which is very nominal by any standards. Despite this, no exporter has exported the subject goods nor did they participate in any of the tenders floated by the customers. Last but not the least, if the stated objective of the said exporter is to eventually establish a manufacturing facility in India, it is far from clear as to why they are interested in opposing the anti-dumping duties. Despite categorical questioning by the Designated Authority during the course of the public hearing, SGPL is silent on the issue. This clearly establishes the ulterior and nefarious intent of the said party.

Submissions by the responding foreign producer

67. The following are the submissions made by SGPL with regard to likely export price, likelihood of continuance or recurrence of dumping and likelihood of continuance or recurrence of injury:
- (i) For the purpose of likely export price to India, the Authority should consider weighted average price of exports from China to the rest of the world instead of taking the export price to a few selected countries, as suggested by the Domestic Industry.
 - (ii) Calculations done to establish likely injury and dumping to the domestic industry are based on mere assumptions without substantiating the same with proper facts and evidence.
 - (iii) Construction of export price is erroneous as the domestic industry has deducted ocean freight and insurance from the FOB import data collected from some Chinese agency.
 - (iv) Domestic Industry has not provided details regarding excess capacity available with the Chinese exporters as also not clarified as to whether it is talking about current capacity or capacity in the next 1 or 2 years. The domestic industry should provide year-wise details of capacity, production, etc. to establish excess capacity in China.
 - (v) SGPL is not a major exporter and hence they would not indulge in dumping once the anti-dumping duties are revoked. Further, they only want to exclude higher diameters pipes from the product scope.
 - (vi) Domestic Industry has not provided valid evidence to prove the likelihood of continuance or recurrence of injury.

- (vii) Saint Gobain is not a major exporter from China. They only want cessation of anti-dumping duties on higher diameter pipes for seed marketing. They further admit that they have no significant price advantage to flood Indian market with subject goods.
- (viii) Due to logistics difficulties, it is very difficult to export DI pipes to India. Saint Gobain only wants to export subject goods of higher diameters which, according to them, are not manufactured in India.
- (ix) It is further submitted that no other country has levied anti-dumping duty on the product under consideration from China. Therefore, there is no need to extend the period of duties.
- (x) India is not a price attractive market because of the internal competition among the domestic producers. Further, the Chinese products are more expensive as compared to the Indian producers. In view of this, it is most likely that no Indian consumer will buy the subject goods from China. Even Chinese exporters will not make any money with such low prices being offered in the Indian market and given the custom duty and the freight.

Examination by the Authority

- 68. While the questionnaire response filed by SGPL has not been accepted by the Authority for reasons already explained above, the Authority has dealt with their submissions to the extent considered relevant.
- 69. In the present investigations, it is important to note that none of the producers/exporters from the subject country, except SGPL, has filed the questionnaire response. Only SGPL, who is not a significant exporter from China even to other countries, has filed the partial response. However, since the company is not a significant exporter of the product under consideration and further since the Designated Authority is required to determine likelihood of dumping and injury considering the volume of exports which were at dumped price and volume of exports which were at injurious price, individual questionnaire response is of limited consequence to such an extent. The likelihood of dumping and injury is required to be determined on the basis of total exports from China to various countries globally.
- 70. Further, as per SGPL's own admission, they are not a major exporter of the subject goods. Therefore, the price data of SGPL cannot be considered as indicative of the likely behaviour of other major producers, let alone a conclusive factor. The Authority notes that the data and information of SGPL cannot be considered as representative for analyzing the likelihood analysis.
- 71. All other interested parties who could have given valuable information to the Authority have preferred not to cooperate with the Authority in the present investigations. The Authority notes that the relevant information from the interested

parties is more important in sunset review investigations where an assessment of likelihood is required to be made.

72. In the response submitted by the domestic industry, they have used the import data of HS International Inc (impexp.com) - Sydney, Australia to estimate the likely export price to India in view of the fact that there have been no imports reported to India either as per the DGCI&S data or in the import data from secondary sources. They have submitted that export price to Saudi Arabia may be considered as the most appropriate by the Authority as China exports 32% of D I Pipes to Saudi Arabia and the significance of water distribution is similar in the two countries. The Authority does not find any merit in this submission made by the Domestic Industry and considers exports to world as per the transaction wise data of HS International Inc (impexp.com) - Sydney, Australia. As regards the submission of SGPL that only the weighted average price to rest of the world should be taken into consideration for the purpose of estimating the likely export price to India, the Authority notes that even if weighted average price of exports from China to globally is above normal value, the same does not mean that dumping from China is unlikely in the event of cessation of anti dumping duty, particularly in a situation where a significant part of these exports are at dumped prices and are likely to cause injury to the domestic industry. Thus, any determination made on the basis of weighted average price of exports could be highly misleading. The facts of the present case in fact have established that even when weighted average price of exports is above normal value, a significant portion of these exports are at dumped and injurious price. The Authority thus considers to take into account the average export price of dumped and injurious transactions from China to all countries (other than India).

73. The Authority considers it appropriate to take into account the average export price of dumped and injurious transactions from China to all countries (other than India) based on the transaction-wise exports data submitted by the domestic industry from HS International Inc (impexp.com) - Sydney, Australia. The Authority has adopted this method because in the absence of actual exports to India, the Authority is determining the likely export price at which subject goods if diverted to India are likely to cause dumping and injury to the domestic industry.

74. The likely ex-works export price of the exports from China PR is determined by the Authority by making appropriate adjustments to the likely net export price on account of inland freight and insurance, commission, port expenses, bank charges and VAT adjustment. After making these adjustments, the likely adjusted ex-factory export price proposed to be determined is as US\$ 683 per MT.

Likely Dumping Margin during POI

	US\$ (per MT)
Normal Value	***

Net Export Price	***
Likely Dumping Margin	***
Likely Dumping Margin %	***
Likely Dumping Margin% Range	0-10

75. For the purpose of determining likelihood of dumping and injury, the Authority has analyzed the transaction wise export prices of Chinese producers to countries other than India as submitted by the Domestic Industry from HS International Inc (impexp.com) - Sydney, Australia.
76. From the data/information available with the Authority, it is noted that the total volume of exports from China PR to other countries during the POI was 4,88,530 MT at an average FOB price of Rs 39,196 per MT, out of which 1,13,641 MT (23%) was at dumped prices as well as at prices which are lower than the non-injurious price of the Domestic Industry. The demand of the subject goods in India during the POI was 6,64,628 MT. This 23% of the total exports from China which are at dumped as well as injurious prices constitute 17% of the total demand in India. This 17% is substantial volume and assumes great significance considering the fact that there is huge capacity available in China; none of the major producers/exporters from China as well as importers in India have responded to the investigation and if the total demand in India is seen, there is every likelihood that if the anti-dumping duties are revoked, the percentage of dumped as well as injurious exports to India are likely to increase and take away major portion of the Indian demand. Further, even if the export behaviour and production capacity of the only responding interested party SGPL is seen, it is noted that as per the information available with the Authority, the known capacity of SGPL is 17,00,000 MT and the production during the POI is only 3,25,367 MT. This leaves surplus capacity of 13,74,633 MT with SGPL alone which is almost double the demand in India. This available surplus capacity can be utilised by SGPL for likely exports to India at the minimum dumped and injurious export price to the world so determined above.
77. The Domestic Industry has provided the information with regard to the capacities available in China in respect of the following producers/exporters:

Sl.No.	Plant	Production Capacity (in MT)
1	Xing Xing Pipe Co.	18,00,000
2	Benxi Beitai Pipe Co.	6,00,000
3	Longkhau Fanlin Pipe Co.	2,50,000
4	Saint Gobain(xuzhou) Pipe Casting Co., Ltd.	17,00,000
5	Dalian Kunda Pipe Co.(2)	

6	Jincheng Chunchen Xinghui Industries Ltd	1,80,000
7	Sun Pipelines Co. Ltd.	1,50,000
8	Xuzhou Everbright Ductile Iron Pipes Co Ltd	2,00,000
9	Shandong Ductile Iron Pipes Co Ltd	3,00,000
10	Rizhao Zhufu Industry Co.Ltd	2,00,000
11	Qian'an Shi Jintang Iron Pipes Co, Ltd	90,000
12	Shanxi Guanghua Casting Pipe Co Ltd	3,00,000
13	Yongtong Ductile Cast Iron Pipes Co Ltd	4,00,000
14	Xinjiang Treasury Ductile Iron Pipes Co Ltd	2,00,000
15	GRAND TOTAL	65,20,000

78. On the basis of the information made available by the Domestic Industry from the websites of some producers/exporters as also other reliable websites of some other producers/exporters, it is seen that the Chinese producers/exporters have ample production capacities with them. They are also exporting Ductile Iron Pipes around the world. No other interested party has either controverted the information or provided any counter-factual information. Moreover, it is noted that the interested parties have failed to give any additional factual information which they wanted the Authority to consider while determining the issue of excess capacities. Thus, there is ample evidence to conclude that the Chinese producers have substantial production capacities. These capacities are in themselves more than the total production capacity of the domestic industry. The importance of such huge production capacities and exports by the Chinese producers/exporters cannot be ignored.
79. Considering the facts available on record with regard to the likely prices to India and the fact that there are huge production capacities in China and that none of the major producers/exporters from China as well as importers in India have responded to the investigation, the Authority determines that if the existing duties are removed, there is every likelihood of the subject goods coming to India at dumped prices which are further likely to cause injury to the domestic industry.
80. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority determines that:
- The constructed Normal Value and the likely net export price to India clearly indicate the likelihood of dumping from China PR if the existing duties are allowed to be revoked.

- (ii) The likely export prices from China PR clearly indicate the likelihood of injury to the Domestic Industry in the form of price undercutting as shown below.

Likely Under Cutting During POI

	US\$(per MT)
NSR	***
Landed Value (Likely)	***
Likely Under Cutting Margin	***
Likely Under Cutting Margin%	***
Likely Under Cutting Margin% Range	5-15

- (iii) The likely export prices from China also clearly indicate the likelihood of injury to the Domestic Industry in the form of price underselling as shown below.

Likely Under Selling During POI

	US\$(per MT)
NIP	***
Landed Value (Likely)	***
Likely Under Selling Margin	***
Likely Under Selling Margin%	***
Likely Under Selling Margin %Range	0-10

- (iv) Further, by taking likely prices to India from the same data, the injury margin is also positive.
- (v) Based on the analysis of information on production capacity of the subject goods of the Chinese producers/exporters; non-cooperation of the major Chinese producers/exporters in the investigation and the price attractiveness of the domestic market in India, there is every likelihood that if the duties are revoked, the volume of dumped and injurious exports from China to India is likely to increase and likely to cause injury to the domestic industry.

J. Indian Industry's Interest

81. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair

competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured by using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

K. Post Disclosure Statement Submissions by the Interested Parties

K.1 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

82. In view of their submissions made on the PUC and legal position in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority is requested to maintain the stand that scope of product cannot be changed/alterd in the sunset review investigations.

K.2 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

83. Only SGPL made the post Disclosure Statement submissions which, in brief, are as follows:
- a. The company may be considered as cooperative exporter;
 - b. Normal value and dumping margin in respect of exports by the company may be determined on the basis of questionnaire response of the company;
 - c. Ductile iron pipes above 1100 mm dia may be exempted from the scope of the product under consideration;
 - d. The Authority may hold that the petitioners have not established that dumping in significant volumes is likely to occur in the event of cessation of anti dumping duty;
 - e. The Authority may hold that the domestic industry is already suffering injury without imports;
 - f. The Authority may hold that the domestic industry is unlikely to suffer injury from imports in the event of cessation of anti dumping duty on imports from Saint-Gobain China.
 - g. Saint Gobain has earlier responded to the notice of initiation and provided all relevant information. Saint-Gobain remains fully committed to totally cooperate with the Designated Authority.

K. 3 Examination by the Authority

84. The Authority notes that the post Disclosure Statement submissions by Domestic Industry are essentially with regard to the product under consideration. The Domestic Industry has contended that on the basis of submissions made on the product under consideration and legal position in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority is requested to maintain the stand that scope of product cannot be changed/altered in the sunset review investigations. The Authority has dealt with all these submissions and legal position appropriately in this Notification under the heading "Product Under Consideration and the Like Article". Other submissions made by the domestic industry and submissions made by SGPL have also been addressed in relevant part of these Findings. The Authority reiterates that since SGPL is admittedly not a major exporter of the product under consideration from China, the information provided by the company is not useful in determining likelihood of dumping and injury from China in the event of cessation of anti dumping duty.

L. Conclusion and Recommendation

85. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and the opposing interested party and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority concludes and recommends that:

- i) The scope of the product under consideration and the recommendation in the present sunset review cover **Ductile Iron Pipes** of all diameters.
- ii) There is clear evidence that if **the existing duties** are allowed to be revoked, the volume of dumped and injurious exports of the subject goods from the subject country to India is likely to increase and likely to cause injury to the domestic industry. The volume of such dumped and injurious exports is significant considering demand for the product under consideration in India. There is every likelihood of dumping and consequential injury to the domestic industry from China PR if the existing duties are allowed to be revoked.
- iii) The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti dumping duty levied by the Central Government vide its Notification No. 103/2007-Customs dated 14th September, 2007 on all imports of Ductile Iron Pipes of **all diameters** from the subject country.

M. Further Procedure

86. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. S. DEEPAK, Designated Authority